रायपुर

रविवार 25 अक्टूबर 2026

वर्ष-07, अंक-297

पृष्ठ-08, मूल्य- दो रुपए

छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश एवं नई दिल्ली से एक साथ प्रकाशित दैनिक समाचार-पत्र

हमारा उद्देश्य सेवा समर्पण जनकल्याण

एक सत बुलेटिन

E-mail: eksatbulletin@gmail.com

Website: www.eksatbulletin.in

न्यूज इन शॉर्ट

मिडिल ईस्ट में तनाव- एयर इंडिया का बड़ा फैसला, रियाद-दम्माम के लिए 7 नवंबर तक उड़ानें रद्द



नई दिल्ली। रियाद और दम्मम से आने-जाने वाली एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानें 7 नवंबर तक निलंबित रहेंगी, जबकि जेद्दा से आने-जाने वाली सेवाएं 31 अक्टूबर तक निलंबित रहेंगी।एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने शनिवार को रियाद और दम्माम के लिए अपनी-अपनी उड़ानें सात नवंबर तक रद्द रखने की घोषणा की जबकि जेद्दा के लिए सेवाएं 31 अक्टूबर तक निलंबित रहेंगी। बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और खाड़ी देशों के हवाई अड्डों पर हुए हमलों के बीच इंडिगो और अकासा एयर ने भी सऊदी अरब के शहरों के लिए अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं।

दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, कई हिस्सों में बारिश से बढ़ी गुलाबी ठंड



नई दिल्ली।मौसम विभाग के मुताबिक नवंबर के पहले सप्ताह में नए वेदर सिस्टम के कारण हरियाणा और दिल्ली-एनसीआर के आसमान में फिर से घने बादल छा सकते हैं और गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। दिल्ली-हृष्टक्रके कई इलाकों में शनिवार रात तेज हवाओं के साथ बारिश की वजह से मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। मौसम में अचानक आए इस बदलाव का असर ्त्ब्ब्र पर भी देखने को मिलेगा। आज हवा की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद की जा रही है। मौसम विशेषज्ञ के मुताबिक, अक्टूबर के अंतिम दिनों और नवंबर की शुरुआत में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसकी वजह से हरियाणा, एनसीआर और दिल्ली में मौसम में बदलाव के साथ बारिश हो सकती है।

राजस्थान पंचायत चुनाव में 80.09 प्रतिशत मतदान



नई दिल्ली।राजस्थान में कुल 3,314 ग्राम पंचायतों में वोटिंग हुई, जिसमें सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ रहे 16 हजार से अधिक उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा. पंच के 28,682 पदों के लिए भी मतदान हुए। राजस्थान में पंच और सरपंच पदों के चुनाव के पहले चरण के तहत 16 जिलों की 3,314 ग्राम पंचायतों में शनिवार को 80।09 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया। वोटिंग ज्यादातर शांतिपूर्ण रही। हालांकि कुछ जगहों पर छोटी-मोटी झड़पें, विरोध प्रदर्शन और बोगस वोटिंग के आरोप लगे। यहां सरपंच के 3,314 पदों के लिए कुल 16,795 उम्मीदवार मैदान में हैं।

जम्मू में धान के खेत में मिला संदिग्ध ड्रोन, इलाके में हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस



नई दिल्ली।शनिवार को जम्मू के काना चक सेक्टर के मख्याल गांव में धान के खेत में एक संदिग्ध ड्रोन मिला, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने ड्रोन को अपने कब्जे में लिया है।जम्मू-कश्मीर के कानाचक सेक्टर में शनिवार को धान के एक खेत में ड्रोन मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ड्रोन को अपने कब्जे में ले लिया। जानकारी के मुताबिक, शाम करीब 4ः40 बजे मखियाल गांव के रहने वाले विजय कुमार के धान के खेत में यह ड्रोन पड़ा हुआ मिला। ने तुरंत कानाचक पुलिस स्टेशन को इसकी सूचना दी।





मुख्यमंत्री ने रामचंडी मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली एवं सुख-समृद्धि की कामना की

एक सत बुलेटिन ➤ रायपुर

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज महासमुंद जिले के बसना विकासखंड अंतर्गत ग्राम गढ़फुलझर में बाबा बिसाशहे कुल कोलता समाज द्वारा आयोजित वार्षिक स्नेह सम्मेलन एवं बंधु मिलन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे।मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सर्वप्रथम गढ़फुलझर स्थित रामचंडी मंदिर पहुंचकर मां रणेश्वर रामचंडी की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। उन्होंने मां रामचंडी से छत्तीसगढ़ की सुख-समृद्धि, खुशहाली और निरंतर प्रगति के साथ प्रदेशवासियों के मंगलमय जीवन की कामना की।

इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद श्री धर्मेंद्र प्रधान, खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल, विधायक श्री पुरन्दर मिश्रा, विधायक श्री संपत अग्रवाल सहित बाबा बिसाशहे कुल कोलता समाज के पदाधिकारी, समाजजन एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से सांसद श्री धर्मेंद्र प्रधान ने की शिष्टाचार भेंट

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं ओडिशा के संबलपुर से सांसद श्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिष्टाचार भेंट की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने श्री प्रधान का आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर दोनों नेताओं के बीच विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई।

सुशासन और पारदर्शिता के साथ हर वर्ग तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाना हमारी प्राथमिकता : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने गढ़फुलझर में 50 लाख रुपये की लागत से निर्मित सर्वमंगल भवन का किया लोकार्पण

एक सत बुलेटिन ➤ रायपुर

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज महासमुंद जिले के बसना विकासखंड अंतर्गत गढ़फुलझर में बाबा बिसाशहे कुल कोलता समाज द्वारा आयोजित वार्षिक स्नेह सम्मेलन एवं बंधु मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 50 लाख रुपये की लागत से निर्मित सर्वमंगल भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने समाज की मांग पर मंदिर परिसर में 50 लाख रुपये की लागत से भव्य डोम निर्माण की घोषणा भी की।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि वर्ष 2024 में गढ़फुलझर के विकास के लिए किए गए वादे अब धरातल पर साकार हो रहे हैं। सर्वमंगल भवन का निर्माण पूरा होने से सामाजिक एवं सामुदायिक गतिविधियों के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। इसके साथ ही 48 लाख रुपये की लागत से मानसरोवर तालाब के सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। क्षेत्र में लगभग पौने दो किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण भी प्रगति पर है, जिस पर लगभग 3.50 करोड़ रुपये की लागत आएगी।



मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विकास कार्यों से गढ़फुलझर और आसपास के क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होने के साथ सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि गढ़फुलझर में विकास का बदलाव अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों को और गति दी जाएगी।

कोलता समाज ने शिक्षा, कृषि और सामाजिक क्षेत्र में बनाई विशिष्ट पहचान

मुख्यमंत्री श्री साय ने कोलता समाज के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि समाज का राज्य सरकार को सदैव स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद मिलता रहा है। कोलता समाज मेहनतकश, शिक्षित, समृद्ध और सामाजिक मूल्यों के प्रति समर्पित समाज है। कृषि, शिक्षा, सेवा और सामाजिक क्षेत्र में समाज के लोगों ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है।

उन्होंने कहा कि सामाजिक एकता और आपसी सहयोग को मजबूत करने में कोलता समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अपनी प्रगतिशील सोच और सामाजिक चेतना के कारण यह समाज दूसरे समाजों के लिए भी प्रेरणा और मार्गदर्शन का कार्य कर रहा है।

मोदी की गारंटी के संकल्पों को तेजी से पूरा कर रही राज्य सरकार

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के अनुरूप राज्य सरकार जनकल्याण से जुड़े संकल्पों को प्राथमिकता के साथ पूरा कर रही है। सरकार का लक्ष्य विकास और जनकल्याण की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उल्लेख करते हुए कहा कि आवास से वंचित गरीब परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए सरकार तेजी से कार्य कर रही है। प्रदेश में प्रतिदिन लगभग 1,600 आवासों का निर्माण हो रहा है। विशेष पिछड़ी जनजातियों के परिवारों को भी प्राथमिकता के आधार पर आवास स्वीकृत किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महतारी वंदन योजना के माध्यम से पात्र महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जा रही है। इसी प्रकार किसानों से किए गए वादों को पूरा करने के साथ तेंदूपत्ता संग्राहकों, श्रमिकों, युवाओं और समाज के अन्य वर्गों के कल्याण के लिए भी अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं।उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता स्पष्ट है - प्रदेश के प्रत्येक परिवार के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए और विकास का लाभ बिना किसी भेदभाव के हर जरूरतमंद तक पहुंचे।

सुशासन और पारदर्शिता के लिए तकनीक का प्रभावी उपयोग

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए तकनीक का व्यापक उपयोग कर रही है। नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 प्रारंभ की गई है। इसके माध्यम से प्राप्त शिकायतों के निराकरण के लिए समय-सीमा और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है।उन्होंने बताया कि सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से 36 विभागों की लगभग 700 शासकीय सेवाएं नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे लोगों को विभिन्न शासकीय सेवाओं के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों के माध्यम से भी विभिन्न सेवाओं और वित्तीय लेन-देन को सरल एवं सुलभ बनाया जा रहा है।मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक के माध्यम से शासन को नागरिकों के और करीब लाना तथा शासकीय सेवाओं को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना सुशासन सरकार का संकल्प है।

पर्यटन और सिंचाई परियोजनाओं से खुलेंगे विकास एवं रोजगार के नए अवसर

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक आस्था, पुरातात्विक विरासत और समृद्ध संस्कृति से परिपूर्ण है। प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक पर्यटन के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। पर्यटन स्थलों पर आवश्यक सुविधाओं के विस्तार के साथ होमस्टे जैसी व्यवस्थाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिल सकें।

मुख्यमंत्री ने सिरपुर बैराज तथा सिकासेर-कोडार लिंक परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किसानों की समृद्धि और कृषि उत्पादन में वृद्धि का आधार बनेगा। सरकार सिंचाई क्षमता बढ़ाने और किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं को आगे बढ़ा रही है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं संबलपुर सांसद श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि गढ़फुलझर आना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने माँ रामचंडी मंदिर की धार्मिक महत्ता का उल्लेख करते हुए कहा कि यह क्षेत्र आस्था, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहां गुरुद्वारे के निर्माण और लक्ष्मी-नारायण मंदिर के विकास से धार्मिक पर्यटन को भी नई दिशा मिलेगी।श्री प्रधान ने कहा कि बसना अंचल में आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का निरंतर विस्तार हो रहा है।

एआईसीडब्लूए ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी

टाइगर श्रॉफ पर हमले से बॉलीवुड में डर का माहौल

एजेंसी ➤ नई दिल्ली

ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने एक्टर टाइगर श्रॉफ पर गोलीबारी की घटना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है और बॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की सुरक्षा पर चिंता जताई है। पत्र में एसोसिएशन ने कहा है कि बॉलीवुड देश की अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि में महत्वपूर्ण योगदान देता है। फिल्म इंडस्ट्री लाखों लोगों की आजीविका का साधन है और शूटिंग में रुकावट और डर का माहौल फिल्म सेट, स्टूडियो, शूटिंग शेड्यूल और निवेश को प्रभावित करता है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान रोजाना काम करके आजीविका चलाने वाले लोगों को उठाना पड़ता है।पत्र में आशंका जताई है कि



अगर बॉलीवुड के कलाकारों पर इस तरह के हमले जारी रहे और अंडरवर्ल्ड का डर बना रहा, तो फिल्म इंडस्ट्री के बड़े कलाकार और जाने-माने लोग डर के कारण मुंबई छोड़कर दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर हो सकते हैं। इससे फिल्म इंडस्ट्री, हजारों परिवारों की आजीविका, मुंबई की पहचान और देश को बड़ा नुकसान होगा।

अपने भाई से मिलने आया था इंदौर

जानकारी के मुताबिक, प्रांजल करीब पांच दिन पहले ही अपने भाई से मिलने इंदौर आया था। उसका भाई इंदौर में रहकर इलाज करवा रहा है। इसी दौरान मुंबई क्राइम ब्रांच को फायरिंग मामले की जांच के सिलसिले में प्रांजल के इंदौर में होने की जानकारी मिली। इसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने इंदौर क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर कार्रवाई की और उसे हिरासत में ले लिया। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि मुंबई में हुई फायरिंग की घटना में प्रांजल की क्या भूमिका रही है। और कथित साजिश से जुड़े बिंदुओं पर पूछताछ की जा रही है।

संयुक्त ऑपरेशन के बाद मामले में जांच का दायरा बढ़ा

हालांकि मामले में उसकी भूमिका और अन्य आरोपियों से संबंधों को लेकर जांच के निष्कर्ष सामने आना बाकी हैं। कार्रवाई के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर मुंबई रवाना होगी, जहां उससे आगे की पूछताछ की जाएगी। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास करेगी कि फायरिंग की घटना के पीछे किन लोगों की भूमिका थी और हथियारों की व्यवस्था किस तरह की गई थी। इंदौर और मामले में जांच का दायरा बढ़ गया है।

न्यूज इन शॉर्ट



सौर ऊर्जा से रोशन होंगी उम्मीदें, जोरातराई के ग्रामीण जीवन में आएगा उजियारा

रायपुर, सौर ऊर्जा से रोशन होंगी उम्मीदें, जोरातराई के ग्रामीण जीवन में आएगा उजियारा

छत्तीसगढ़ के दूरस्थ ग्रामीण एवं वनांचल क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में धमतरी जिले के ग्राम जोरातराई के सड़क पारा में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र की बैटरियों का प्रतिस्थापन ग्रामीणों के जीवन में सुविधाओं का नया उजियारा लेकर आया है। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) द्वारा की गई इस पहल से सौर ऊर्जा संयंत्र की भंडारण क्षमता बेहतर होगी और ग्रामीण परिवारों को विद्युत सुविधा का अधिक प्रभावी लाभ मिल सकेगा। यह प्रयास न केवल स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित संसाधनों के समुचित रखरखाव और उनकी निरंतर उपयोगिता सुनिश्चित करने का भी उदाहरण है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ग्रामीण एवं वनांचल क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। शासन की इसी पहल के अनुरूप क्रेडा द्वारा सौर ऊर्जा संयंत्रों के संचालन एवं संधारण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को उपलब्ध ऊर्जा सुविधाओं का निरंतर लाभ मिल सके।

धमतरी जिले के ग्राम जोरातराई के सड़क पारा में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र की बैटरियों की क्षमता प्रभावित होने से ऊर्जा भंडारण और विद्युत आपूर्ति में कठिनाई उत्पन्न होने की संभावना थी। इसे ध्यान में रखते हुए क्रेडा द्वारा संयंत्र की पुरानी बैटरियों का प्रतिस्थापन किया गया। इससे संयंत्र की कार्यक्षमता बनाए रखने और सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली का आवश्यकता के अनुरूप उपयोग सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी।

अब शाम ढलने के बाद भी पढ़ाई और घरेलू कार्यों में होगी आसानी ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता केवल प्रकाश का माध्यम नहीं, बल्कि शिक्षा, घरेलू गतिविधियों और बेहतर जीवन स्तर का महत्वपूर्ण आधार है। विशेषकर शाम और रात्रि के समय पर्याप्त रोशनी बच्चों की पढ़ाई तथा परिवारों के दैनिक कार्यों के लिए आवश्यक होती है। ग्राम जोरातराई के सड़क पारा में सौर ऊर्जा संयंत्र की बैटरियां बदले जाने से ग्रामीण परिवारों को इन सुविधाओं का बेहतर लाभ मिलने की उम्मीद है। सौर ऊर्जा व्यवस्था के सुचारु संचालन से विद्यार्थियों को शाम के समय अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। वहीं महिलाओं और अन्य ग्रामीणों को घरेलू कार्यों में सहूलियत होगी। इस प्रकार ऊर्जा संयंत्र का तकनीकी रखरखाव ग्रामीण परिवारों के दैनिक जीवन को अधिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में उपयोगी साबित होगा। स्वच्छ ऊर्जा से पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण विकास को बढ़ावा सौर ऊर्जा पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोत होने के साथ दूरस्थ क्षेत्रों में विद्युत सुविधाओं के विस्तार का महत्वपूर्ण माध्यम भी है। ऐसे क्षेत्रों में जहां पारंपरिक विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता सीमित हो सकती है, वहां सौर ऊर्जा आधारित व्यवस्थाएं ग्रामीण जीवन को सुविधाजनक बनाने में सहायक होती हैं। क्रेडा द्वारा ग्राम जोरातराई में किया गया बैटरी प्रतिस्थापन यह दर्शाता है कि किसी भी विकास कार्य की सफलता केवल नई सुविधाएं स्थापित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका नियमित रखरखाव और लंबे समय तक प्रभावी संचालन सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक है। समय पर तकनीकी सुधार से स्थापित संसाधनों की उपयोगिता बनी रहती है और ग्रामीणों को उनका बेहतर लाभ मिल सकता है।

शासकीय रामानुज प्रताप सिंह देव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैकुंठपुर में विभिन्न समस्याओं को लेकर प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन

इससे विद्यार्थियों की समस्याओं के निराकरण की दिशा में सकारात्मक पहल की उम्मीद जगी है

एक सत बुलेटिन ➤ बैकुंठपुर

विद्यार्थियों के हितों की रक्षा और महाविद्यालय की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) की बैकुंठपुर नगर इकाई के कार्यकर्ताओं ने शासकीय रामानुज प्रताप सिंह देव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैकुंठपुर के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा।इस दौरान कार्यकर्ताओं ने विद्यार्थियों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को महाविद्यालय प्रशासन के समक्ष रखते हुए उनके शीघ्र एवं उचित निराकरण की मांग की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि महाविद्यालय विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास और उज्ज्वल भविष्य के निर्माण का प्रमुख केंद्र है। ऐसे में विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना महाविद्यालय प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।ज्ञापन पर चर्चा के दौरान महाविद्यालय के प्राचार्य ने कार्यकर्ताओं की मांगों एवं समस्याओं पर सकारात्मक आश्वासन दिया।



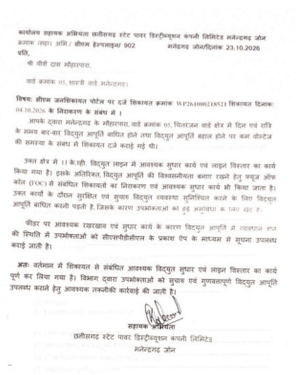
इससे विद्यार्थियों की समस्याओं के निराकरण की दिशा में सकारात्मक पहल की उम्मीद जगी है।अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सदैव छात्रहित, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय भूमिका निभाती रही है। परिषद का उद्देश्य केवल समस्याओं को उठाना ही नहीं, बल्कि उनके समाधान के लिए सकारात्मक पहल करना भी है। इसी उद्देश्य के साथ कार्यकर्ताओं ने महाविद्यालय प्रशासन से विद्यार्थियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया।इस अवसर पर आयुषी साहू (नगर मंत्री), आकांक्षा सिंह (नगर सह मंत्री), सिद्धार्थ साहू (नगर सह मंत्री), अलका सिंह, श्वेता गुप्ता, खुशी राजवाड़े, मनीषा साहू, आकाश एवं कार्तिक सहित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विद्यार्थियों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए समस्याओं के समाधान के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई तथा महाविद्यालय प्रशासन से दिए गए आश्वासन के अनुरूप आवश्यक कदम उठाने की अपेक्षा की।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 की शिकायत का हुआ फिर हुआ असर, विद्युत विभाग ने मानी अपनी गलती...

विभाग ने यह भी उल्लेख किया है। कि सुधार कार्यों के दौरान हुई असुविधा के लिए खेद है

महेंद्र शुक्ला ➤ एमसीबी

मनेन्द्रगढ़ शहर के चितरंजन वार्ड क्र. 05 मौहारपारा क्षेत्र में अघोषित विद्युत कटौती, देर रात अचानक लाइट गुल होने एवं लो वोल्टेज की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर यीशै दास द्वारा की गई थी उक्त शिकायत का बडा असर देखने को मिला है।वहीं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर उक्त समस्या की शिकायत दर्ज कराई थी। जिसका शिकायत का टोकन क्रमांक CG26100021852 1के शिकायत के परिपालन में कार्यालय सहायक अभियंता, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, जोन मनेन्द्रगढ़ ने पत्र क्र. सहा/अभि/सीएम हेल्पलाइन/902 दिनांक 23/10/2026 जारी कर अपना जवाब प्रस्तुत किया है। विभाग ने अपने जवाब में बताया कि क्षेत्र में 11 के.व्ही. विद्युत लाइन में आवश्यक सुधार एवं लाइन विस्तार का कार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति की



विश्वसनीयता बनाए रखने हेतु फ्यूज ऑफ कॉल (स्नह्वष्ट) से संबंधित शिकायतों का भी निराकरण किया गया है। विभाग ने यह भी उल्लेख किया है। कि सुधार कार्यों के दौरान हुई असुविधा के लिए खेद है ।और वर्तमान में शिकायत से संबंधित कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

गौरतलब है कि विभाग द्वारा समय-समय पर मेंटेनेंस के नाम पर कटौती की जाती है, उसके बाद भी बार-बार सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ती है, यह सवाल क्षेत्रवासियों में बना हुआ है।

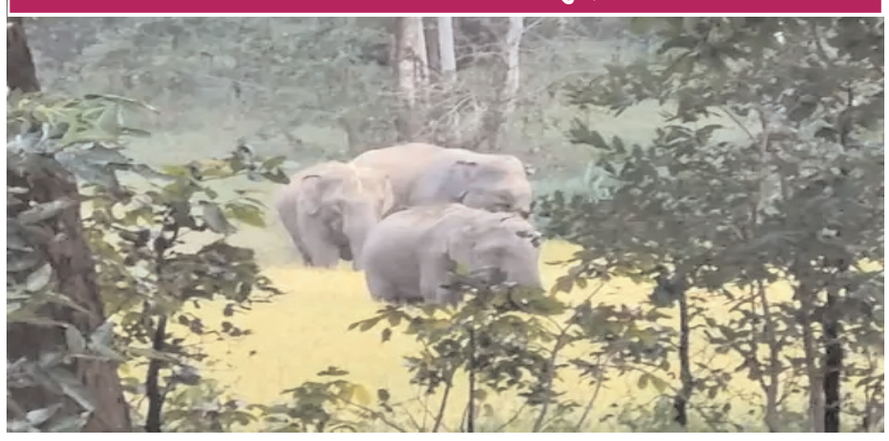
इस संबंध में शिकायतकर्ता यीशै दास ने बताया कि -÷मेरे द्वारा वार्ड 05



मौहारपारा में लगातार अघोषित विद्युत कटौती और लो वोल्टेज की समस्या को मद्देनजर रखते हुए जनहित में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के पोर्टल पर शिकायत की गई थी। संबंधित विभाग ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए 11 ञ्चङ्क लाइन का सुधार कार्य पूर्ण किया है। सुशासन की सरकार में शिकायत पर तत्काल संज्ञान लिया जा रहा है। मुझे उम्मीद है ।कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही नहीं होगी और क्षेत्रवासियों को सुचारू बिजली मिलती रहेगी।÷मेरा प्रयास आगे भी जनहित के मुद्दों को उठाने का रहेगा,

मरवाही में पहुंचे 52 हाथी, फसल को नुकसान की आशंका

पसान में 20 दिन बिताने के बाद मटियाडांड-भटियार पहुंचे; दल में शावक भी शामिल



एक सत बुलेटिन ➤ गौरेला-पेंड्रा-मरवाही

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के मरवाही वनमंडल में हाथियों की आमद से ग्रामीणों और किसानों की चिंता बढ़ गई है। कटघोरा वनमंडल के पसान क्षेत्र में करीब 20 दिन बिताने के बाद 52 हाथियों का दल अब मरवाही के मटियाडांड और भटियार इलाके में पहुंच गया है। हाथियों का झुंड क्षेत्र में अलग-अलग जगहों पर घूम रहा है।शुरुआत में हाथियों के इस दल में 35 से 40 हाथियों के होने का अनुमान लगाया गया था। वन विभाग की गणना के मुताबिक, अब इस दल में कुल 52 हाथी हैं। इनमें कई छोटे शावक भी शामिल हैं, जो बड़े हाथियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

खेतों में धान की फसल खा रहे हाथी

हाथियों का झुंड इलाके के खेतों में लहलहाती धान की फसल खा रहा है। इससे किसानों को फसल के नुकसान की आशंका सता रही है। हाथियों की लगातार आवाजाही से ग्रामीण भी चिंतित हैं।

वन विभाग और हाथी मित्र दल कर रहे निगरानी

हाथियों की गतिविधियों और उनकी सुरक्षा को देखते हुए वन विभाग का मैदानी अमला और हाथी मित्र दल लगातार निगरानी कर रहे हैं। विभाग की ओर से ग्रामीणों को सतर्क रहने और जंगल की तरफ नहीं जाने की सलाह दी जा रही है। इसके लिए गांवों में लगातार मुनादी भी कराई जा रही है।

आरक्षण काउंटरों से आरक्षित टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को भी मिलेगी यात्रा बीमा की सुविधा

एक सत बुलेटिन ➤ बिलासपुर,

यात्रियों की सुविधा एवं यात्रा के दौरान वित्तीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे द्वारा आरक्षण काउंटरों (पीआरएस) से आरक्षित टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को भी यात्रा बीमा की सुविधा उपलब्ध कराने की पहल की गई है। यह सुविधा 27 अक्टूबर 2026 से प्रारंभ होगी।

इस सुविधा के अंतर्गत आरक्षण काउंटर से टिकट बुक कराने वाले यात्री निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार यात्रा बीमा का विकल्प चुन सकेंगे। इसके लिए टिकट बुकिंग के समय डिजिटल माध्यम से भुगतान तथा वैध मोबाइल नंबर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

यात्रा बीमा के अंतर्गत रेल दुर्घटना अथवा पॉलिसी में निर्धारित आकस्मिक घटनाओं की स्थिति में मृत्यु, स्थायी पूर्ण दिव्यांगता, स्थायी आंशिक दिव्यांगता, दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती होने पर चिकित्सा व्यय तथा पार्थिव शरीर के परिवहन के लिए बीमा सुरक्षा का प्रावधान है। बीमा लाभ, बीमा राशि एवं दावों का निपटान संबंधित बीमा कंपनी की पॉलिसी में निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर मंडलों के आरक्षण काउंटरों से टिकट बुक कराने वाले यात्री इस सुविधा का लाभ निर्धारित नियमों एवं शर्तों के तहत उठा सकेंगे।

दिवाली और छठ के दौरान सुरक्षित रेल यात्रा : भीड़ प्रबंधन, अग्रिम योजना और कुशल यात्री-आवागमन प्रबंधन पर जोर

जीआरपी प्रमुखों के सम्मेलन में ड्रोन ‡पिंक पेट्रोल‡ से लेकर प्रोजेक्ट दिशा तक, महिला-नेतृत्व और समुदाय-आधारित सुरक्षा पहलों पर चर्चा हुई



एक सत बुलेटिन ➤ रायपुर

रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) द्वारा आयोजित सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) प्रमुखों का 8वां अखिल भारतीय सम्मेलन 23 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। इसने नई सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करने, श्रेष्ठ व्यवस्था साझा करने और आरपीएफ, जीआरपी और राज्य पुलिस के बीच समन्वय को मजबूत करने के लिए एक मंच प्रदान किया।इस उच्चस्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता आरपीएफ की महानिदेशक सुश्री सोनाली मिश्रा ने की। इसमें रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ श्री सतीश कुमार, रेलवे बोर्ड के सदस्य और अलग-अलग राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जीआरपी प्रमुख शामिल हुए।

इस सम्मेलन की एक प्रमुख विशेषता रेल सूचना प्रणाली केंद्र (क्रिस) द्वारा जीआरपी कर्मचारियों को रेलमदद प्लेटफॉर्म से जोड़ना रही। इसका उद्देश्य यात्री शिकायत निवारण व्यवस्था को बेहतर बनाना, समय पर जानकारी साझा करना और शिकायतों की बेहतर निगरानी करना था।इसमें रेल सुरक्षा और यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न पहलों पर विस्तार से चर्चा की गई।दक्षिण मध्य रेलवे के ÷पिंक पेट्रोल÷ आइज़ इन द स्काई, शक्ति ऑन द ग्राउंड÷ में महिलाओं के नेतृत्व वाला एक मॉडल दिखाया गया, जिसमें शक्ति फ्रेमवर्क के तहत द्रुत कार्यबलों के साथ ड्रोन-से निगरानी को शामिल किया गया।इस सम्मेलन में ट्रेनों पर पत्थरबाजी को एक चुनौती बताया गया और पत्थरबाजी के प्रमुख स्थानों पर गश्ती, बेहतर निगरानी, ??अपराधियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई, युवाओं तक पहुंच और आरपीएफ-जीआरपी के बीच मजबूत तालमेल पर जोर दिया गया। इसके लिए समाज में जागरूकता और रोकथाम के लिए लोगों तक पहुंच को महत्वपूर्ण माना गया।

सम्मेलन में दिवाली, छठ और अन्य त्योहारों के दौरान भीड़ प्रबंधन पर भी चर्चा हुई। उत्तरी रेलवे के दिल्ली मंडल ने दिल्ली पुलिस, जीआरपी और दिल्ली मेट्रो के प्राधिकारियों के साथ मिलकर किए गए कार्या के बारे में बताया। इसमें सीसीटीवी से निगरानी, सार्वजनिक घोषणा, बैरिकेडिंग, निर्धारित ठहराव क्षेत्र और विशेष नियंत्रण कक्ष शामिल थे। व्यस्ततम समय में यात्रियों की सुरक्षा और यात्रियों के व्यवस्थित आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए अग्रिम योजना, प्रभावी यात्री आवागमन प्रबंधन और सुरक्षाकर्मियों की समन्वित तैनाती पर ज़ोर दिया गया।मध्य रेलवे के पुणे मंडल ने प्रोजेक्ट दिशा (सुरक्षा, सामन्जस्य और जागरूकता के लिए समर्पित पहल) के बारे में बताया। यह एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य रेलवे पटरियों के पास रहने वाले बच्चों को शैक्षणिक और मनोरंजनात्मक गतिविधियों, सुरक्षा जागरूकता सत्रों और सामादायिक उपायों के माध्यम से जोड़ना है। गैर-सरकारी संगठनों, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों और स्थानीय समुदायों के सहयोग से रेलवे सुरक्षा और जिम्मेदार व्यवहार के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाती है। साथ ही, पत्थरबाजी, चोरी, अनाधिकृत प्रवेश और अन्य असुरक्षित गतिविधियों को रोकने का प्रयास किया जाता है।सम्मेलन में आरपीएफ और जीआरपी के लिए संयुक्त प्रशिक्षण, तोड़फोड़ की घटनाओं को रोकना, और नशीले पदार्थों का पता चलने पर तुरंत जानकारी साझा करने जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई।

गर्भस्थ शिशु की मौत पर मुवावजे के लिए विधायक ने मुख्यमंत्री से की चर्चा,5लाख की सहायता का मिला भरोसा

केल्हारी बस हादसा- मृतकों के परिजनों से मिलीं रेणुका सिंह,शोकाकुल परिवारों को बंधाया

एक सत बुलेटिन ➤ एमसीबी

केल्हारी क्षेत्र के सेमरमथानी मोड़ पर दो दिन पूर्व हुए भीषण बस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मिलने शनिवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भरतपुर-सोनहत विधायक रेणुका सिंह उनके निवास पहुंचीं। उन्होंने शोकाकुल परिवारों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया तथा दिवंगतों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की।

हादसे में एक गर्भवती महिला के गर्भस्थ शिशु की मृत्यु की पुष्टि होने पर विधायक रेणुका सिंह ने तत्काल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से दूरभाष पर चर्चा की। उन्होंने मुख्यमंत्री को घटना की जानकारी देते हुए पीड़ित महिला को भी 5 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करने का



आग्रह किया। इस पर मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि संबंधित महिला को भी 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।

गौरतलब है कि इस भीषण बस दुर्घटना के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपये तथा घायलों को 50 हजार रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की थी। गर्भवती महिला के साथ हुई दुखद घटना को ध्यान में रखते हुए विधायक ने उसके लिए भी आर्थिक सहायता सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

इससे पूर्व शुक्रवार को विधायक रेणुका सिंह मनेंद्रगढ़ स्थित 220 बिस्तरीय सिविल अस्पताल पहुंची थीं, जहां उन्होंने हादसे में घायल लोगों और उनके परिजनों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने घायलों के बेहतर उपचार के लिए हरसंभव सहयोग का आश्वासन देते हुए स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया था कि इलाज में किसी प्रकार की कमी न हो तथा सभी घायलों को समुचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

हादसे से प्रभावित परिवारों के दुख में सहभागी बनते हुए विधायक रेणुका सिंह ने हरसंभव सहायता का भरोसा दिलाया।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल की OTS-2 योजना को बड़ी सफलता, अब तक 62.5 प्रतिशत संपत्तियों का विक्रय

मंडल आयुक्त श्री अवनीश कुमार शरण ने की योजना की समीक्षा, शेष आवासों में लिफ्ट, मरम्मत और मूलभूत सुविधाएं दुरुस्त करने के दिए निर्देश

एक सत बुलेटिन ➤ रायपुर



छत्तीसगढ़ में आम नागरिकों को किफायती दरों पर आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियां उपलब्ध कराने तथा वर्षों से रिक्त पड़ी संपत्तियों के बेहतर उपयोग की दिशा में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल की वन टाइम सेटलमेंट योजना-2 (ह्वञस-2) महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व एवं आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन में संचालित इस योजना के अंतर्गत अब तक 62.5 प्रतिशत संपत्तियों का विक्रय किया जा चुका है। योजना के माध्यम से कुल 251.71 करोड़ रुपये मूल्य की 1,659 आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियों का विक्रय हुआ है।

ह्वञस-2 योजना के अंतर्गत कुल 2,656 संपत्तियों को विक्रय के लिए शामिल किया गया था। इनमें से अब केवल 997 संपत्तियां विक्रय के लिए शेष हैं, जिनका कुल मूल्य 134.40 करोड़ रुपये है। योजना की सफलता से जहां वर्षों से रिक्त पड़ी संपत्तियों का उपयोग सुनिश्चित हो रहा है, वहीं आम नागरिकों को रियायती दरों पर अपना घर एवं व्यावसायिक परिसर प्राप्त करने का अवसर भी मिल रहा है।

पूर्ववर्ती योजना की तुलना में ह्वञस-2 का प्रदर्शन बेहतर

वन टाइम सेटलमेंट योजना-2 की उपलब्धि पूर्व में संचालित ह्वञस योजना की तुलना में उल्लेखनीय रही है। सितंबर 2021 से मार्च 2024 तक संचालित पूर्ववर्ती वन टाइम सेटलमेंट योजना के अंतर्गत लगभग 511 करोड़ रुपये मूल्य की 2,591 आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियों को शामिल किया गया था। इस अवधि में कुल 88.28 करोड़ रुपये मूल्य की 506 संपत्तियों का विक्रय हुआ था, जिसमें विक्रय का प्रतिशत 17.27 रहा था। वहीं वर्तमान ह्वञस-2 योजना में अब तक 62.5 प्रतिशत संपत्तियों का विक्रय हो चुका है।इस प्रकार पूर्ववर्ती योजना की तुलना में वर्तमान योजना के विक्रय प्रतिशत में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल की संपत्ति विक्रय व्यवस्था में आए सकारात्मक बदलाव तथा रियायती दरों पर संपत्तियां उपलब्ध कराने की नीति के प्रभावी परिणामों को दर्शाती है।

मंत्रिपरिषद के निर्णय से मिली योजना को गति

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 19 जनवरी 2025 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल की पांच वर्ष से अधिक समय से अविक्रित आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियों के एकमुश्त निपटान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था। इसके अंतर्गत ऐसी संपत्तियों को लागत मूल्य (बेस रेट) पर निर्धारित छूट प्रदान कर विक्रय करने की स्वीकृति दी गई थी।

मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुरूप 1 मार्च 2025 से वन टाइम सेटलमेंट योजना-2 प्रारंभ की गई। योजना में संपत्तियों के रिक्त रहने की अवधि तथा संबंधित परियोजना में रिक्त संपत्तियों के अनुपात के आधार पर 10, 20 एवं 30 प्रतिशत तक छूट का प्रावधान किया गया है। इस पहल से लंबे समय से अविक्रित संपत्तियों के विक्रय को गति मिली है तथा नागरिकों के लिए आवास एवं व्यावसायिक संपत्ति खरीदने के नए अवसर उपलब्ध हुए हैं।

मंडल आयुक्त ने की समीक्षा, शेष संपत्तियों के विक्रय में तेजी लाने के निर्देश

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के मुख्यालय में 23 अक्टूबर को मंडल आयुक्त श्री अवनीश कुमार शरण ने ह्वञस-2 योजना की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की।

तीन जिलों में 2.70 करोड़ रुपये से बनेंगे भवन, विभागीय सेवाओं और योजनाओं के मैदानी क्रियान्वयन को मिलेगी मजबूती

मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के प्रयासों से छह परियोजना-सह-संसाधन केंद्रों के भवनों को मंजूरी

एक सत बुलेटिन ➤ रायपुर



मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य शासन महिलाओं और बच्चों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं को मजबूत आधारभूत सुविधाओं के साथ जमीनी स्तर तक पहुंचाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के प्रयासों से प्रदेश के छह परियोजना-सह-संसाधन केंद्रों के भवन निर्माण को स्वीकृति मिली है। राज्य शासन ने इन भवनों के लिए कुल 2 करोड़ 70 लाख 90 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रथम किस्त के रूप में 67 लाख 72 हजार 500 रुपये जारी करने की सहमति भी दी गई है।

नए भवन सूरजपुर जिले के भैयाथान और ओड़गी, रायगढ़ जिले के तमनार तथा बीजापुर जिले के बीजापुर, उसूर और भोपालपटनम में बनाए जाएंगे। प्रत्येक भवन के निर्माण के लिए 45 लाख 15 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

महिला एवं बाल विकास विभाग महिलाओं और बच्चों के विकास, स्वास्थ्य, पोषण तथा उनके अधिकारों और हितों के संरक्षण से जुड़ी अनेक योजनाओं और सेवाओं का संचालन करता है। परियोजना-सह-संसाधन केंद्र इन योजनाओं के मैदानी क्रियान्वयन, विभागीय अमले के समन्वय और सेवाओं की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप भवनों का निर्माण विभागीय कार्यों के संचालन के लिए बेहतर और व्यवस्थित सुविधा उपलब्ध कराएगा।

यह स्वीकृति केवल भवन निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि महिला एवं बाल विकास सेवाओं को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बेहतर आधारभूत सुविधा से विभागीय अमले को योजनाओं के क्रियान्वयन और हितग्राहियों से जुड़े कार्यों में सहूलियत मिलेगी। साथ ही, महिलाओं और बच्चों तक शासन की कल्याणकारी योजनाओं तथा सेवाओं की पहुंच आसान बनाने में मदद मिलेगी। दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में विभागीय गतिविधियों को मजबूत करने से शासन की जनकल्याणकारी पहलें अधिक व्यवस्थित रूप से लोगों तक पहुंच सकेंगी।

शासन के आदेश के अनुसार, अगली किस्त के प्रस्ताव के साथ प्रथम किस्त के उपयोग का प्रमाण-पत्र तथा निर्माण कार्य की भौतिक और वित्तीय प्रगति का विवरण प्रस्तुत करना होगा। स्वीकृत राशि का उपयोग निर्धारित व्यय सीमा और शासन के नियमों के अनुरूप किया जाएगा।

दुख के दौर में शारदा को मिला श्रम विभाग की योजना का सहारा

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना से दिवंगत श्रमिक के परिवार को मिली 05 लाख रुपए की आर्थिक मदद

एक सत बुलेटिन ➤ रायपुर



छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग अंतर्गत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवारों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संचालित मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत कोंडागांव जिले के एक श्रमिक परिवार को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। जिला व तहसील कोंडागांव के ग्राम सातगांव, नानीपदर निवासी श्री धनेश बघेल श्रम विभाग में इलेक्ट्रीशियन के रूप में पंजीकृत निर्माण श्रमिक थे। कार्यस्थल से घर लौटने के दौरान सड़क दुर्घटना में उनका असामयिक निधन हो गया।शासन की योजना के तहत पात्रता एवं आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण होने पर उनकी पत्नी एवं उत्तराधिकारी श्रीमती शारदा बघेल को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इस सहायता से दिवंगत श्रमिक के परिवार को दुख के कठिन और प्रतिकूल समय में आर्थिक संबल प्राप्त हुआ। छत्तीसगढ़ शासन एवं श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों और उनके आश्रित परिवारों के हितों की रक्षा तथा विपरीत परिस्थितियों में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग ने श्रमिकों से अपील की है कि शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपना पंजीयन अद्यतन रखें तथा योजनाओं की पात्रता एवं आवेदन प्रक्रिया की जानकारी संबंधित श्रम कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना से प्रदेश के श्रद्धालुओं को मिल रहा निःशुल्क तीर्थ दर्शन का अवसर

एक सत बुलेटिन ➤ रायपुर



मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के माध्यम से प्रदेश के श्रद्धालुओं को प्रमुख तीर्थस्थलों के निःशुल्क दर्शन का अवसर मिल रहा है। योजना के तहत जांजगीर-चांपा जिले के 277 तीर्थयात्रियों को चांपा रेलवे स्टेशन से पुरी, कोणार्क और भुवनेश्वर की यात्रा के लिए रवाना किया गया। यह यात्रा 23 से 26 अक्टूबर तक आयोजित की जा रही है। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष इंजी. सत्यलता आनंद मिरी, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती उमा राजेन्द्र राठौर एवं श्री राज कुमार साहू, नगर पालिका अध्यक्ष श्री प्रदीप नामदेव, इंजी. रवि पांडेय सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया और तीर्थयात्रियों को मंगलमय यात्रा की शुभकामनाएं दीं।

जिला पंचायत अध्यक्ष इंजी. सत्यलता आनंद मिरी ने कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना बुजुर्गों और जरूरतमंद लोगों के लिए लाभकारी है। योजना के माध्यम से श्रद्धालुओं को देश के प्रमुख तीर्थस्थलों के दर्शन का अवसर मिल रहा है। चार दिवसीय यात्रा के दौरान तीर्थयात्री पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करेंगे। इसके साथ ही वे कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर और भुवनेश्वर के प्रमुख धार्मिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। यात्रा के दौरान प्रशासन द्वारा भोजन, चिकित्सा, ठहरने और सुरक्षा की व्यवस्था की गई है।

परसा गांव में बनेंगे प्राथमिक और माध्यमिक शाला के नए भवन, डीएमएफ से 33.90 लाख की राशि स्वीकृत

रायगढ़, रायगढ़ जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में शिक्षा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में धरमजयगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत बैरागी के आश्रित ग्राम परसा में प्राथमिक और माध्यमिक शाला के नए भवन बनाए जाएंगे। जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) से दोनों भवनों के निर्माण के लिए कुल 33 लाख 90 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। इससे गांव के बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर और सुविधायुक्त भवन उपलब्ध हो सकेगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप तथा वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक श्री ओ.पी. चौधरी की पहल पर जिले में शिक्षा सहित बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए डीएमएफ की राशि का उपयोग किया जा रहा है। परसा में नए स्कूल भवनों का निर्माण इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

ग्राम तुमड़ीबहार में महिलाओं को दिया गया शहद प्रसंस्करण का व्यावहारिक प्रशिक्षण

एक सत बुलेटिन ➤ धमतरी,



जिले के वनांचल क्षेत्र में महिलाओं को आजीविका के नए अवसरों से जोड़ने तथा स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग को प्रोत्साहित करने की दिशा में ग्राम तुमड़ीबहार, विकासखंड नगरी में महिलाओं को शहद प्रसंस्करण (हनी प्रोसेसिंग) का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य महिलाओं को शहद के प्रसंस्करण, गुणवत्ता बनाए रखने, सुरक्षित पैकेजिंग तथा विपणन के लिए आवश्यक तकनीकी जानकारी देकर स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ना है।कृषि विज्ञान केंद्र के डॉ. अमित सिन्हा ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागी महिलाओं को शहद प्रसंस्करण में उपयोग होने वाली मशीनों के संचालन, रखरखाव और उनके सुरक्षित उपयोग की जानकारी दी गई। इसमें शहद गर्म करने, छानने, स्थिरीकरण तथा पैकेजिंग से संबंधित इकाइयों के संचालन का व्यावहारिक अभ्यास कराया गया। महिलाओं ने फिल्टर को जोड़ने, उसके सही उपयोग तथा सफाई की प्रक्रिया भी सीखी। इससे उन्हें शहद को स्वच्छ एवं व्यवस्थित तरीके से प्रसंस्कृत करने की तकनीकी समझ विकसित करने में मदद मिलेगी। इससे पूर्व, 17 सितंबर 2026 को भी इसी प्रकार का एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया था।

उन्होंने बताया कि शहद प्रसंस्करण का कौशल ग्रामीण महिलाओं के लिए आजीविका का एक उपयोगी माध्यम बन सकता है। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध शहद का उचित प्रसंस्करण, आकर्षक पैकेजिंग और बाजार की मांग के अनुरूप विक्रय करने से उत्पाद का बेहतर मूल्य प्राप्त करने की संभावनाएं बढ़ती हैं। महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सामूहिक रूप से यह गतिविधि अपनाकर स्थानीय बाजारों, दुकानों, मेलों तथा अन्य संभावित विक्रय माध्यमों तक अपनी पहुंच बना सकती हैं। इससे स्वरोजगार के अवसर सृजित होने के साथ परिवार की आय बढ़ाने और महिलाओं की आर्थिक भागीदारी मजबूत करने में मदद मिल सकती है। कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों पर आधारित आजीविका गतिविधियों को प्रोत्साहित करना तथा महिलाओं को व्यावहारिक कौशल से सशक्त बनाना महत्वपूर्ण है।

बैगा महिलाओं को लघु वनोपज के संग्रहण, विपणन, समूह संचालन एवं स्वरोजगार का दिया गया प्रशिक्षण

विकसित भारत 2047 के संकल्प की दिशा में जनजातीय सशक्तीकरण पर जोर

एक सत बुलेटिन ➤ खैरागढ़



जनजातीय कार्य मंत्रालय के निर्देशानुसार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में जनजातीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने तथा उनके सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण के उद्देश्य से जिले में विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में कलेक्टर कार्यालय के आदिम जाति विकास विभाग के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत सिंगारपुर के ग्राम बैगापारा (तुमड़ाबोड़) में बैगा जनजाति की महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को आजीविका के बेहतर अवसरों से जोड़ना, उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना तथा उपलब्ध स्थानीय संसाधनों के माध्यम से आय के साधनों को सुदृढ़ करना रहा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), वन विभाग एवं उद्योग विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा महिलाओं को विभिन्न आजीविका गतिविधियों के संबंध में जानकारी एवं मार्गदर्शन प्रदान किया गया। महिलाओं को समूह संचालन, सामूहिक आजीविका गतिविधियों, लघु वनोपज के संग्रहण एवं क्रय-विक्रय, तेंदूपत्ता संग्रहण तथा विपणन की प्रक्रियाओं से अवगत कराया गया। इसके साथ ही बीमा संबंधी जानकारी देकर उन्हें उपलब्ध सुरक्षा एवं बीमा प्रावधानों के प्रति जागरूक किया गया। उद्योग विभाग द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार एवं आजीविका संवर्धन से जुड़ी गतिविधियों के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं को स्थानीय वन संसाधनों के बेहतर उपयोग, सामूहिक प्रयासों से आजीविका गतिविधियों के संचालन तथा लघु वनोपज के विपणन की प्रक्रियाओं को समझने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम जनजातीय महिलाओं की क्षमता वृद्धि, आर्थिक भागीदारी एवं आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं।

कार्यक्रम में सरपंच श्री चंद्र कुमार वर्मा, सचिव श्री तेजनाथ ठाकुर, लघु वनोपज प्रबंधक श्री चंद्रेश्वर यादव, जूनियर एग्जीक्यूटिव खैरागढ़ श्री संजय पटेल, ठाकुरटोला एवं कुम्हारवाड़ा के प्रबंधक श्री चेतन दास, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जनपद पंचायत छुईखदान के ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर तथा वन विभाग एवं उद्योग विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रशिक्षण में सक्रिय महिलाओं, एफएलसीआरपी एवं ग्रामीणों ने सहभागिता की। जनजातीय समुदायों का आर्थिक सशक्तीकरण, स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग तथा आजीविका के अवसरों का विस्तार विकसित भारत 2047 के व्यापक संकल्प की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

न्यूज इन शॉर्ट

मारकंडी नदी से शहर तक पहुंचेगा पानी, बस्तर जलप्रदाय योजना के लिए 57.71 करोड़ मंजूर

जल शोधन संयंत्र, उच्च स्तरीय जलागार और नए वितरण नेटवर्क से सुनिश्चित की जाएगी शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, जून-2028 तक पूरी होगी योजना

अमृत मिशन 2.0 से शहर की पेयजल व्यवस्था का होगा कायाकल्प - श्री अरुण साव

रायपुर, राज्य शासन ने बस्तर नगर पंचायत में शुद्ध और सुरक्षित पेयजल के लिए नई जलप्रदाय योजना को मंजूरी दी है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के राज्य शहरी विकास अभिकरण (स्ष्ब) ने अमृत मिशन 2.0 के अंतर्गत बस्तर की नई जलप्रदाय योजना के लिए 57 करोड़ 71 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। इस महत्वाकांक्षी योजना के पूरा होने के बाद शहर में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल की उपलब्धता मौजूदा 65 लीटर से बढ़कर 135 लीटर हो जाएगी। यानी हर व्यक्ति को रोजाना 70 लीटर अतिरिक्त शुद्ध पेयजल मिल सकेगा।

योजना के तहत शहर में करीब 73 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी और 2700 से अधिक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। इससे शहर में पेयजल वितरण व्यवस्था मजबूत होने के साथ ही लोगों को घरों तक पर्याप्त शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। बस्तर जलप्रदाय योजना के लिए मारकंडी नदी के चपका एनीकट में इंटेकवेल का निर्माण किया जाएगा। वहां से रॉ-वॉटर पाइपलाइन के जरिए नदी का पानी जल शोधन संयंत्र तक पहुंचाया जाएगा। संयंत्र में पानी के शुद्धिकरण के बाद इसे बस्तर शहर में पेयजल आपूर्ति के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इस तरह नदी से पानी लेने, उसका शुद्धिकरण करने और घरों तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था विकसित की जाएगी। बस्तर की इस नई जलप्रदाय योजना से शहर की पेयजल व्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। वर्तमान में वहां प्रत्येक व्यक्ति को औसतन 65 लीटर प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध हो रहा है। नई योजना के पूर्ण होने पर यह मात्रा बढ़कर 135 लीटर प्रतिदिन हो जाएगी। इससे घरेलू जरूरतों के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और नागरिकों को पर्याप्त शुद्ध पेयजल मिलेगा। योजना का काम जून-2028 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

योजना के अंतर्गत तीन एमएलडी क्षमता का जल शोधन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही 500 किलोलीटर क्षमता का एक उच्च स्तरीय जलागार भी बनाया जाएगा। शहर में पेयजल वितरण के लिए 73 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। जल शोधन संयंत्र, उच्च स्तरीय जलागार और नए वितरण नेटवर्क के माध्यम से शहर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने की व्यवस्था तैयार की जाएगी। इसके पूरा होने से बस्तर शहर के नागरिकों को अधिक मात्रा में शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा और शहर की पेयजल अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी। योजना के लिए स्वीकृत राशि में पांच वर्षों तक संचालन एवं संधारण भी शामिल है।

ऊबस्तर नगर पंचायत में सभी परिवारों को पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अमृत मिशन 2.0 से शहर की पेयजल व्यवस्था का कायाकल्प होगा। हमारी सरकार का संकल्प है कि हर परिवार को बुनियादी सुविधाएं सुलभ हों और लोगों का जीवन अधिक सुविधाजनक बने। बस्तर की यह पहल इसी संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। - श्री अरुण साव, उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री

बस्तर जलप्रदाय परियोजना के क्रियान्वयन में उच्च तकनीकी मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। निर्माण के प्रत्येक चरण की नियमित निगरानी और प्रगति की सतत समीक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया है। योजना के कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही और अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी घटकों का निर्माण निर्धारित गुणवत्ता के साथ जून-2028 की समय-सीमा में पूर्ण करने के लिए जवाबदेही तय की जाएगी।

आईआईटी भिलाई के छठे दीक्षांत समारोह में 313 विद्यार्थियों को मिली उपाधियाँ, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थी स्वर्ण पदक से सम्मानित

छत्तीसगढ़ में नवाचार, अनुसंधान और रोजगार के नए अवसर विकसित कर रहा आईआईटी भिलाई

एक सत बुलेटिन ➤ रायपुर



आईआईटी भिलाई के छठे दीक्षांत समारोह में 313 विद्यार्थियों को मिली उपाधियाँ, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थी स्वर्ण पदक से सम्मानित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) भिलाई के नालंदा हॉल में आज छठा दीक्षांत समारोह गरिमामय वातावरण में आयोजित हुआ। समारोह में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के कुल 313 विद्यार्थियों को उपाधियाँ प्रदान की गईं। उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए प्रतिभावान विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक एवं सीनेट पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में नीति आयोग के पूर्व सदस्य एवं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के पूर्व महानिदेशक डॉ. विजय कुमार सारस्वत उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता आईआईटी भिलाई के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष प्रो. वीरेंद्र कुमार विजय ने की।

समारोह का शुभारंभ अकादमिक शोभायात्रा के साथ हुआ। आईआईटी भिलाई के निदेशक प्रो. राजीव प्रकाश ने स्वागत उद्बोधन देते हुए संस्थान की वार्षिक उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आईआईटी भिलाई छत्तीसगढ़ को प्रौद्योगिकी, नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

छत्तीसगढ़ का पहला आईटी पार्क बना नवाचार और रोजगार की नई संभावनाओं का केंद्र निदेशक प्रो. राजीव प्रकाश ने बताया कि आईआईटी भिलाई और छत्तीसगढ़ शासन की संयुक्त पहल से राज्य का पहला आईटी पार्क स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा सिविल लाइंस में उद्घाटित यह आईटी पार्क प्रदेश में तकनीकी नवाचार, स्टार्टअप, उद्यमिता और रोजगार सृजन को नई दिशा देने की महत्वपूर्ण पहल है। संस्थान का लक्ष्य छत्तीसगढ़ में विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान इकोसिस्टम विकसित करना है।

'जीराफूल चावल से समृद्धि की नई राह, चांगरो के किसानों को मिलेगा बेहतर बाजार'

एक सत बुलेटिन ➤ रायपुर



छत्तीसगढ़ की पारंपरिक कृषि पहचान को सहेजने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए बलरामपुर जिले के ग्राम चांगरो में जीराफूल चावल की जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन ने गांव पहुंचकर किसानों तथा स्व-सहायता समूहों की महिलाओं से चर्चा की। उन्होंने जीराफूल की खेती को संगठित रूप देने, इसकी ब्रांडिंग करने और किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए विशेष कार्ययोजना बनाने का भरोसा दिलाया। ग्रामीणों के साथ आत्मीय संवाद के दौरान जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने जमीन पर बैठकर किसानों के अनुभव सुने और पारंपरिक खेती को सहेजने के उनके प्रयासों की सराहना की। किसानों को रासायनिक खाद से दूरी बनाकर जैविक पद्धति अपनाने के लिए प्रेरित किया।उन्होंने कहा कि चांगरो का जीराफूल चावल क्षेत्र की अनमोल पहचान है। इसकी सुगंध और गुणवत्ता को जिले से आगे राज्य और देशभर में पहुंचाने के लिए हरसंभव सहयोग किया जाएगा।

जीराफूल पारंपरिक, सुगंधित और छोटे दाने वाली धान की किस्म है। इसके पतले दाने जीरे जैसे दिखते हैं, इसलिए इसका नाम जीराफूल पड़ा। मार्च 2019 में इसे जीआई टैग मिला। प्राकृतिक मिठास और मनमोहक सुगंध के लिए प्रसिद्ध यह चावल हल्का और सुपाच्य भी है। बाजार में इसकी कीमत लगभग 100 से 120 रुपये प्रति किलो तक है।

जिला प्रशासन ने बताया कि जीराफूल की बेहतर मार्केटिंग और उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए किसानों के साथ मिलकर कार्ययोजना बनाई जाएगी। शंकरगढ़ क्षेत्र के लगभग 30 गांवों में इसकी खेती हो रही है। उत्पादन क्षेत्र का विस्तार करने के साथ चांगरो के जीराफूल चावल की प्रभावी ब्रांडिंग पर भी काम किया जाएगा।

'सेवा सेतु' केन्द्र के माध्यम से दिलीप कुमार को एक दिन में मिला जाति प्रमाण पत्र

एक सत बुलेटिन ➤ रायपुर



आम नागरिकों को शासकीय सेवाओं का त्वरित एवं पारदर्शी लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 'सेवा सेतु' केन्द्र जमीनी स्तर पर बेहद कारगर साबित हो रहा है। इसके माध्यम से नागरिकों को आवश्यक दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने से निजात मिल रही है। बालोद जिले के ग्राम मुल्झेगुड़ा निवासी श्री दिलीप के लिए यह अत्यंत मददगार साबित हुआ, जहां उन्हें मात्र एक ही दिवस के भीतर उनका जाति प्रमाण पत्र तैयार कर प्रदान कर दिया गया।

एक दिन में प्रक्रिया पूर्ण, दूर हुई लंबे इंतजार की चिंता

हितग्राही श्री दिलीप कुमार ने बताया कि उन्हें विभिन्न आवश्यक कार्यों एवं योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए जाति प्रमाण पत्र की अत्यंत आवश्यकता थी। पूर्व में प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कई दिनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी तथा बार-बार कार्यालयीन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था। लेकिन सेवा सेतु केन्द्र के तहत जब उन्होंने अपने दस्तावेज प्रस्तुत किए, तो संबंधित अमले ने पूरी संवेदनशीलता एवं तत्परता दिखाते हुए आवेदन का त्वरित सत्यापन किया और रिकॉर्ड समय में मात्र एक दिन के भीतर उनका जाति प्रमाण पत्र तैयार कर उन्हें सौंप दिया।

समयबद्ध सेवा से आमजन में बढ़ा विश्वास

एक ही दिन में बिना किसी परेशानी के प्रमाण पत्र मिलने पर दिलीप की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने बताया कि इस त्वरित पहल से न केवल उनके समय और धन की बचत हुई, बल्कि शासकीय व्यवस्था के प्रति उनका विश्वास और अधिक सुदृढ़ हुआ है। सेवा सेतु के माध्यम से सुशासन की जो परिकल्पना साकार हो रही है, वह ग्रामीण अंचल के जरूरतमंद लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।

'मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में कृषक उन्नति योजना से फसल विविधीकरण को मिल रहा बढ़ावा, किसानों के लिए खुल रहे आय के नए

एक सत बुलेटिन ➤ रायपुर



मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित कर रही है। राज्य शासन की कृषक उन्नति योजना किसानों को परंपरागत धान की खेती के साथ वैकल्पिक एवं अधिक लाभकारी फसलों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। योजना के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि से किसानों को खेती में नए प्रयोग करने और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने का अवसर मिल रहा है। इसी पहल से प्रेरित होकर सरगुजा जिले के युवा किसान अभिषेक सिंह ने धान के स्थान पर अदरक की खेती अपनाकर फसल विविधीकरण की दिशा में कदम बढ़ाया है।

सरगुजा जिले की दरिमा तहसील अंतर्गत ग्राम लिबरा निवासी युवा किसान अभिषेक सिंह, पिता श्री मदन सिंह, पूर्व में अपनी कृषि भूमि पर मुख्य रूप से धान की खेती करते थे। इस वर्ष उन्होंने अपनी लगभग आधा एकड़ भूमि में धान के स्थान पर अदरक की फसल लगाई है। अभिषेक सिंह को उम्मीद है कि अदरक की खेती से उन्हें धान की तुलना में बेहतर आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। उनका यह प्रयास दर्शाता है कि शासन की प्रोत्साहन योजनाओं से प्रेरित होकर किसान परंपरागत खेती के साथ नई संभावनाओं की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 'अदरक की खेती से बेहतर आमदनी की उम्मीद' युवा किसान अभिषेक सिंह बताते हैं कि खेती को अधिक लाभकारी बनाने के लिए नई फसलों और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाना आवश्यक है। इसी सोच के साथ उन्होंने इस वर्ष धान के स्थान पर अदरक की खेती करने का निर्णय लिया। उन्हें उम्मीद है कि अदरक की अच्छी पैदावार और बाजार में उचित मूल्य मिलने से उनकी आमदनी बढ़ेगी। हालांकि, फसल की बिक्री के बाद ही वास्तविक लागत और मुनाफे का आकलन हो सकेगा। उनका मानना है कि शासन की ओर से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि किसानों को वैकल्पिक फसलों की खेती अपनाने के लिए अतिरिक्त आर्थिक संबल प्रदान करती है।

'प्रति एकड़ 15 हजार रुपये तक प्रोत्साहन राशि का मिलेगा लाभ' कृषक उन्नति योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अभिषेक सिंह दरिमा स्थित सहकारी समिति में पंजीयन कराने पहुंचे। उन्होंने बताया कि जिस भूमि पर पहले धान की खेती करते थे, उसी भूमि पर इस वर्ष अदरक की फसल लगाई है। योजना के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों एवं पात्रता के अनुसार धान के स्थान पर वैकल्पिक फसल लेने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये तक प्रोत्साहन राशि का लाभ मिल सकता है। अभिषेक सिंह को भी पंजीयन एवं पात्रता संबंधी प्रक्रिया पूर्ण होने पर योजना का लाभ मिलने की उम्मीद है।

'सहकारी समितियों में पंजीयन जारी, किसानों को किया जा रहा जागरूक'

कृषक उन्नति योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र किसानों तक पहुंचाने के लिए सरगुजा जिले की सभी सहकारी समितियों में पंजीयन का कार्य जारी है। कृषि विभाग द्वारा किसानों को योजना के प्रावधानों, पात्रता और फसल विविधीकरण से होने वाले लाभों की जानकारी दी जा रही है। किसानों को धान के स्थान पर वैकल्पिक फसलों की खेती अपनाने तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पंजीयन कराने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

राज्य शासन की मंशा है कि किसान परंपरागत खेती के साथ स्थानीय जलवायु, मिट्टी और बाजार की मांग के अनुरूप लाभकारी फसलों को अपनाएं, जिससे कृषि उत्पादन में विविधता आने के साथ उनकी आय में भी वृद्धि हो सके। सरगुजा के युवा किसान अभिषेक सिंह की पहल इसी दिशा में एक सकारात्मक उदाहरण है। जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे कृषक उन्नति योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी नजदीकी सहकारी समिति से संपर्क कर पात्रता एवं पंजीयन संबंधी जानकारी प्राप्त करें और निर्धारित समय-सीमा में पंजीयन सुनिश्चित कराएं। फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने की यह पहल किसानों की आर्थिक आत्मनिर्भरता और प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

20 प्रमुख मार्गों के डामरीकरण के लिए 24 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति, समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूर्ण करने के निर्देश

कोरबा की प्रमुख सड़कों के डामरीकरण कार्य का शुभारंभ, उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने किया निरीक्षण

एक सत बुलेटिन ➤ रायपुर

कोरबा की प्रमुख सड़कों के डामरीकरण कार्य का शुभारंभ, उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने किया निरीक्षण

कोरबा शहर की प्रमुख सड़कों को बेहतर एवं सुगम बनाने की दिशा में डामरीकरण कार्य शनिवार से प्रारंभ हो गया। उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन एवं महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत ने कार्यस्थल पर जाकर वहां चल रहे डामरीकरण कार्यों का अवलोकन तथा निरीक्षण कर नगर निगम के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उल्लेखनीय है कि उद्योग मंत्री श्री देवांगन के प्रयासों से कोरबा नगर निगम क्षेत्र के 20 प्रमुख मार्गों के सड़क डामरीकरण कार्यों के लिए करीब 24 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। इन विकास कार्यों का भूमिपूजन 19 अक्टूबर को कोसाबाड़ी चौक पर संपन्न हुआ था। इसके पश्चात शनिवार को सोनालिया पुल से ओवरब्रिज मार्ग पर डामरीकरण कार्य प्रारंभ किया गया।





निरीक्षण के दौरान उद्योग मंत्री ने नगर निगम अधिकारियों को निर्देशित किया कि शहर के सभी स्वीकृत डामरीकरण कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि नागरिकों को बेहतर एवं सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके। साथ ही निर्माण कार्यों को व्यवस्थित ढंग से पूर्ण करने और आम नागरिकों को आवागमन में अनावश्यक परेशानी न हो, इसका भी ध्यान रखने के निर्देश दिए। इस अवसर पर नगर निगम के अधीक्षण अभियंता, प्रभारी कार्यपालन अभियंता, एमआईसी सदस्य श्री नरेंद्र देवांगन, श्री चंद्रलोक सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे।

साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के 6 विकेट गिरे



एजेंसी ➤ डरबन

ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेशन में 3 विकेट गंवाए। ट्रैविस हेड 19 गेंदों पर 9 रन बनाकर आउट हुए। वियान मुल्डर की गेंद लेग स्टंप के बाहर से बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर काइल वेरेने के दस्तानों में गई। अंपायर ने पहले उन्हें नॉटआउट दिया, लेकिन साउथ अफ्रीका के रिव्यू लेने पर फैसला बदल गया।इसके बाद निक मैडिनसन भी खाता खोले बिना पवेलियन लौट गए। वह 33 गेंदों तक कोई रन नहीं बना सके। मार्को यानसन की गेंद पर बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और वह आउट हो गए। मैडिनसन 10 साल बाद टेस्ट टीम में वापसी कर रहे थे। इससे पहला उनका आखिरी टेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ दिसंबर 2016 था।

तीसरे विकेट के रूप में मार्नस लाबुशेन आउट हुए। वह 37 रन बनाकर खेल रहे थे। मुल्डर की अंदर आती गेंद उनके पैड पर लगी। अंपायर ने उन्हें आउट दिया और लाबुशेन ने रिव्यू लिया, लेकिन फैसला नहीं बदला। वह लगातार 11वीं टेस्ट पारी में अर्धशतक लगाने में नाकाम रहे।मैडिनसन के आउट होने के बाद स्टीव स्मिथ क्रीज पर आए। उनके आते ही एनरिक नॉर्त्या को गेंदबाजी पर लगाया गया, जिससे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को तेज रफ्तार और उछाल का सामना करना पड़ा।स्मिथ ने केशव महाराज के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया और उनके दूसरे ओवर में लगातार दो छक्के लगाए। इस दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ के टेस्ट रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया और देश के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाजों में तीसरे स्थान पर पहुंच गए।

हालांकि, लंच के बाद स्मिथ की पारी ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकी। यानसन ने राउंड द विकेट से गेंदबाजी करते हुए उन्हें गली में कैच करा दिया। स्मिथ ने 25 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने इस तरह अपने शीर्ष क्रम के चार विकेट गंवा दिए।साउथ अफ्रीका ने इसके बाद भी अपनी लाइन और लेंथ बनाए रखी। मैट रेनशॉ के खिलाफ यानसन की एक उछाल भरी गेंद पर कैच की अपील हुई, लेकिन गेंद दस्ताने के बजाय उनके फोरआर्म से लगी थी।

पीवी सिंधु फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंचीं



डबल ओलिंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने शनिवार को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में जापान की हिना अकीची को हराया।31 साल की सिंधु ने वर्ल्ड नंबर-22 अकीची को 21-10, 20-22, 21-16 से मात दी। यह मुकाबला एक घंटे 13 मिनट चला। फाइनल में सिंधु का सामना कोरिया की वर्ल्ड नंबर-1 एन से यंग से होगा। सिंधु ने इससे पहले जुलाई में जापान ओपन का खिताब जीता था।

भारत के खिलाफ टी-20 में सबसे बड़ा रनचेज



एजेंसी ➤ नई दिल्ली

रांची। भारत के खिलाफ टी-20 में सबसे बड़ा रनचेज हो गया है। वेस्टइंडीज ने दूसरे मैच में 6 विकेट खोकर 250 रन का टारगेट हासिल कर लिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 2023 में 223 रन चेज किए थे।रांची में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 249 रन बनाए। संजू सैमसन ने 41 बॉल पर 82 रन बनाए। उनके अलावा ईशान किशन ने 43 रन की पारी खेली। तिलक वर्मा 44 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने आखिरी ओवर में लगातार 3 सिक्स लगाए। कप्तान श्रेयस अय्यर ने 40 रन बनाए।

जवाब में वेस्टइंडीज ने 18.3 ओवर में 4 विकेट खोकर 252 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। कप्तान शाई ने 45 बॉल पर नाबाद 102 रन की पारी खेली। शेरफेन रदरफोर्ड ने 37 बॉल पर 84 रन बनाए। रोमारियो शेफर्ड 13 बॉल पर 34 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत से मयंक यादव ने 3 विकेट लिए। कुलदीप यादव को एक विकेट मिला।

शाई होप ने 45 गेंदों में शतक जड़ा, वेस्टइंडीज जीतावेस्टइंडीज ने 250 रन का टारगेट 18.3 ओवर में हासिल कर इतिहास रच दिया। टीम ने 6 विकेट से मुकाबला जीतकर 5 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। कप्तान शाई होप ने सिर्फ 45 गेंदों में शतक पूरा किया। यह उनका टी-20 में दूसरा शतक है।

भारत ने दूसरे टी20 में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया

तिलक-नीतीश ने न्यूजीलैंड के जबड़े से छीनी जीत

एजेंसी ➤ नई दिल्ली

लोग या तो टीवी-मोबाइल बंद कर चुके थे या बस सिर झुकाए देखे जा रहे थे। कुछ बचा ही नहीं था। 31 बॉल में 69 रन बनाने थे। 6 विकेट गिर गए थे। क्या ही होता।किन तिलक और नीतीश मैदान पर थे। बस इन्हीं दोनों को लग रहा होगा कि चलो कुछ तूफानी करते हैं। और फिर अगले 40 मिनट क्रीज पर रहे, 30 बॉल में 69 रन बना डाले। बस एक बॉल बची थी मैच की और दौड़कर दो रन ले लिए। नीतीश ने आधी पिच से ही भींची हुई बाईं मुट्ठी ऊपर कर बता दिया कि जीत गए हम।

सामने न्यूजीलैंड की टीम थी। फील्ड क्राइस्टचर्च का था। लक्ष्य 181 रन का था। भारतीय टीम 14.5 ओवर में 112 रन पर 6 विकेट गंवा चुकी थी। तिलक और नीतीश ने यहीं से मोर्चा संभाला। तिलक ने 26 गेंदों में 51 और नीतीश ने 13 गेंदों पर 26 रन बनाए। न्यूजीलैंड को 4 विकेट से



हराया। बढ़त 2-0 की हो गई है। कुल 5 टी-20 होने हैं।18 ओवर खत्म होने के बाद भारत के 152 रन थे। 6 बल्लेबाज आउट हो चुके थे। क्रीज पर तिलक वर्मा और नीतीश रेड्डी थे। 19वां ओवर डालने पहुंचे न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर नाथन।

तिलक ने पहली गेंद पर चौका मार दिया। दूसरी गेंद पर भी नसीब से चौका मिला। तीसरी गेंद चूक गए, लेकिन चौथी गेंद पर चौका मार दिया। पांचवीं गेंद ने फिर चकमा दिया। छठी गेंद पर तिलक ने छक्का लगाया, तो स्टेडियम में मौजूद लोगों के साथ भारतीय खिलाड़ी भी तालियां बजाते दिखे।

अब आखिरी ओवर बचा, चाहिए थे 11 रन। स्ट्राइक पर नीतीश और सामने कीवी पेसर जैकब डफी। पहली गेंद पर सिंगल लेकर तिलक को स्ट्राइक दी। तिलक ने आते ही चौका मार दिया। तीसरी बॉल पर दौड़कर दो रन लिए। अपनी फिफ्टी पूरी की।

व्यापार

फेस्टिव सीजन में कारों का धमाका



नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अक्टूबर में कई लॉन्चेज होने वाले हैं. फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए तमाम कंपनियों ने अपनी तैयारी कर ली हैं। टोयोटा, होंडा, हुंडई, स्कोडा और रेनो अपनी नई कारों को इस महीने मार्केट में उतारने वाले हैं। इस महीने हमें 5 मास मार्केट गाड़ियां देखने को मिलेंगी। इस लिस्ट में हैचबैक से लेकर एसयूवी और सेडान तक शामिल हैं। ऐसे में नई कार खरीदने वालों को थोड़ा इंतजार कर लेने से बेहतर विकल्प या बेहतर डील दोनों मिल सकती है।

इंडिगो में कल से सफर महंगा, फ्यूल चार्ज बढ़ाया

एजेंसी ➤ नई दिल्ली

1300, इंटरनेशनल में देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की फ्लाइट्स मंगलवार से महंगी हो जाएंगी। एयरलाइन ने घरेलू उड़ानों में ?1300 तक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स में ?10,000 तक एक्स्ट्रा फ्यूल चार्ज लगाने का ऐलान किया है। नई कीमतें 6 अक्टूबर रात 12ः01 बजे से लागू होंगी।इंडिगो ने छह महीने में तीसरी बार फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया है। इससे पहले एयरलाइन ने इस साल 14 मार्च और फिर 1 अप्रैल को किराया बढ़ाया था। एयरलाइन के मुताबिक, यह फैसला एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी जेट फ्यूल महंगा होने से लिया गया है।कंपनी ने किराया बढ़ाने का फैसला हवाई जहाजों में इस्तेमाल होने वाला फ्यूल महंगा होने की वजह से लिया है। 1 अक्टूबर से घरेलू



एयरलाइंस के लिए कीमत ?121 से बढ़कर अब ?137 हो गई है। यानी 1 लीटर ञ्जस्र की कीमत 16 रुपए (करीब 13.2ञ्) बढ़ गई है।इंडिगो के अनुसार, पिछले एक ही महीने में जेट फ्यूल के दाम 14ञ् से ज्यादा बढ़ चुके हैं। इसके चलते प्लेन में डलने वाला तेल अब पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा महंगा हो गया है।

एयरलाइंस के लिए सबसे बड़ा खर्च होता है जेट-फ्यूलजेट फ्यूल की कीमतें बढ़ने के चलते दुनियाभर की एयरलाइंस ने न सिर्फ टिकट के दाम बढ़ा दिए हैं, बल्कि अपने भविष्य के वित्तीय अनुमानों यानी फाइनेंशियल आउटलुक को भी वापस लिया है। एयरलाइंस के लिए जेट-फ्यूल सबसे बड़ा खर्च होता है। से 40ञ् होती है।

अब बिना कोर्ट-ऑर्डर अरेस्ट नहीं कर पाएंगे; GST कानून में सुधार की तैयारी

टैक्स अधिकारियों से छिनेगा गिरफ्तारी का अधिकार

एजेंसी ➤ नई दिल्ली

जीएसटी काउंसिल 7 अक्टूबर को होने वाली अपनी बैठक में देश के इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में बड़े सुधारों को मंजूरी दे सकती है। नए प्रस्ताव के तहत टैक्स अधिकारियों से सीधे गिरफ्तार करने का अधिकार वापस लेने और फर्जीवाड़े के आपराधिक मामलों की सीमा बढ़ाने की तैयारी है।सितंबर 2025 में हुए रेट रेशनलाइजेशन यानी ञ्जस्र दरों में बदलाव के बाद सरकार अब नेक्स्ट-जनरेशन जीएसटी के तहत टैक्स प्रशासन को आसान बनाने और कारोबारियों को राहत देने पर काम कर रही है।ताव लाया जा रहा है?

जवाबः नए प्रस्ताव के तहत सीजीएसटी एक्ट की धारा 69 में संशोधन की तैयारी है। अब तक कमिश्नर लेवल की मंजूरी मिलने पर जीएसटी अधिकारी किसी व्यक्ति को सीधे गिरफ्तार कर सकते थे।नए बदलाव के बाद



अधिकारियों से यह पावर वापस ले ली जाएगी। अब किसी भी गिरफ्तारी के लिए कोर्ट (न्यायिक मंजूरी) का आदेश अनिवार्य होगा।

सवालः क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की सीमा में क्या बदलाव होगा?

जवाबः वर्तमान में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स चोरी या फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम के मामलों में आपराधिक कार्रवाई और गिरफ्तारी की व्यवस्था है।

प्रस्ताव के अनुसार, क्रिमिनल केस चलाने की इस लिमिट को ?1 करोड़ से बढ़ाकर सीधे ?5 करोड़ करने की सिफारिश की गई है। यानी ?5 करोड़ से कम के मामलों में आपराधिक केस दर्ज नहीं होगा।

सवालः क्या रूटीन टैक्स विवादों में भी अब जेल जाना पड़ सकता है?

जवाबः नहीं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि क्लासिफिकेशन, वैल्यूएशन या इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूटीन विवादों को क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के दायरे से बाहर रखा जाएगा।कई बार किसी एक ट्रांजैक्शन की परिभाषा को लेकर बिजनेस और टैक्स अधिकारियों की राय अलग-अलग हो सकती है, ऐसे मामलों को अब क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाएगा।सवालः जीएसटी अधिकारियों से अरेस्ट पावर वापस लेने की मुख्य वजह क्या है?

जवाबः जब 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था, तब फेक इनवॉइस और टैक्स चोरी पकड़ने के लिए ऑटोमेटेड सिस्टम मजबूत नहीं था। इसलिए गिरफ्तारी का डर जरूरी था। अब जीएसटी का सिस्टम बहुत मजबूत हो चुका है।

अमेरिका-भारत ट्रेड डील की बातचीत में अब ज्यादा गुंजाइश नहीं



एजेंसी ➤ नई दिल्ली

भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर चल रही बातचीत ऐसी जगह पर आकर अटक गई है, जहां से आगे बढ़ना दोनों देशों के लिए मुश्किल हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को नई दिल्ली में आयोजित म्यूनिख लीडर्स मीटिंग के दौरान यह बात कही। ।उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच बात उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां न तो भारत और छूट देने को तैयार है, और न ही अमेरिका। वित्त मंत्री ने कहा फिर भी अगर आगे बातचीत का कोई नया रास्ता निकलता है या गुंजाइश बनती है, तो दोनों देश उस पर बात करने के लिए तैयार हैं।

व्यापार समझौते में हर देश चाहता है कि उसके किसानों, कंपनियों और व्यापारियों का नुकसान न हो। एक हद के बाद कोई भी देश अपनी शर्तों से पीछे नहीं हटना चाहता। इसका मतलब यह नहीं है ।



वोटर नाम' का घोटाला

चुनाव आयोग की एक और करतूत सामने आई है। इसे मतदाता सूची शुद्धिकरण के नाम पर 'बड़ा घोटाला' करार दिया जा सकता है। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया में मतदाताओं के नाम ही बदल दिए गए। अथवा उनके पिता का नाम ही बदल दिया गया। यह करतूत मतदाता सूची के अंतिम संस्करण के प्रकाशन के बाद सामने आई है। ऐसे कई और मामले भी हो सकते हैं कि आम मतदाता आश्वस्त होगा कि अंततः वह मतदाता बन गया है, सूची में उसका नाम दर्ज हो गया है, लेकिन जब चुनाव होंगे और वह मतदान करने जाएगा, तो सूची में कोई और नाम होगा! वह अपना सिर पीट लेगा। चुनाव अधिकारी से बहस भी करेगा और अपना मतदाता पहचान-पत्र भी दिखाएगा, लेकिन चुनाव अधिकारी के लिए तो मतदाता सूची ही मान्य और वैध दस्तावेज है। देश का मतदाता असहाय है। यह चुनाव आयोग आखिर कर क्या रहा है उसके मंसूबे क्या हैं क्या वाकई वह लोकतंत्र को कुतर रहा है? कांग्रेस ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ बेहद गंभीर और संवेदनशील खुलासे किए हैं। उप्र की पीलीभीत सदर विधानसभा सीट का ही उदाहरण लें, तो कोई भी चौंक सकता है। इस क्षेत्र में 13,150 मतदाताओं के नाम बदल दिए गए हैं, हालांकि मतदाता पहचान-पत्र के 'एपिक' और सीरियल नंबर यथावत हैं। इस क्षेत्र की मतदाता सूची से 804 नाम गायब कर दिए गए हैं, जबकि वे लोग अब भी वहीं रहते हैं।करीब 2600 ऐसे नाम सूची में जोड़े गए हैं, जो उस क्षेत्र के निवासी ही नहीं हैं। बताया गया है कि एक ही विधानसभा क्षेत्र में 16,554 मतदाताओं के नाम को लेकर गड़बड़झाला किया गया है। इस संदर्भ में कांग्रेस ने प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करा दी है। बेशक यह अवैध और आपराधिक करतूत है, जो मानवीय गलती के कारण हुई या चुनाव आयोग के सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ की गई! जांच-पड़ताल में यह तथ्य भी सामने आया है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में 124 सीटों पर करीब 10,000 मतों से ही जीत-हार हुई थी। जीतने वाले अधिकतर भाजपा उम्मीदवार थे।

(एक नजर)

धनतेरस पर तिथि-मुहूर्त देखकर करें खरीदारी

दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही बाजारों में रौनक बढ़ने लगती है. पांच दिनों तक चलने वाले इस त्योहार की शुरुआत धनतेरस से होती है. इस दिन लोग सोना, चांदी, बर्तन और दूसरी चीजें खरीदते हैं. मान्यता है कि धनतेरस पर खरीदारी करने से घर में सुख-समृद्धि आती है. इस दिन भगवान धन्वंतरि, मां लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा भी की जाती है. अगर आप भी धनतेरस पर खरीदारी करने की सोच रहे हैं, तो पहले इसकी तारीख और शुभ मुहूर्त जान लें. ऐसे में आइए जानते हैं कि साल 2026 में धनतेरस कब मनाया जाएगा और पूजा व खरीदारी के लिए शुभ समय क्या रहेगा. धनतेरस 2026 में कब है? द्रिक पंचांग के अनुसार, धनतेरस का त्योहार हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है. साल 2026 में यह तिथि 6 नवंबर को सुबह 09 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगी, जिसका समापन 7 नवंबर को सुबह 11 बजकर 45 मिनट पर होगा. ऐसे में धनतेरस 6 नवंबर, शुक्रवार को मनाया जाएगा. धनतेरस पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त द्रिक पंचांग के अनुसार, इस साल धनतेरस पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त 6 नवंबर को सुबह 9 बजकर 30 मिनट के बाद शुरू होगा. इसके बाद आप अपनी सुविधा के अनुसार खरीदारी कर सकते हैं।

विचार

महंगाई का रावण

- ललित गर्ग

लेखक

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उक्त घोषणा करने से पूर्व हिमाचल की आर्थिक स्थिति, केंद्र के व्यवहार तथा सरकार के विभिन्न प्रयासों का जिक्र किया है। यह मानना पड़ेगा कि सरकार को चलाने का सबसे अधिक खर्चा सरकारी कर्मचारी व पेंशनभोगियों के खाते में जाता है। सरकार अपने चौथे वर्ष की लागत में मनोहारी होने का हर रंग आजमा सकती है और इसकी एक शुरुआत हम महंगाई की किस्त में देख सकते हैं।

इस बार दिवाली के दीप सरकारी कर्मचारियों को सुखद एहसास देंगे। कम से कम हिमाचल सरकार ने महंगाई के रावण को मारने के लिए कर्मचारियों को कुल पांच प्रतिशत डीए की किस्त दी है। कर्मचारी आशाओं का सूखापन महंगाई भत्ते की आदायगी से कितना हरा होता है, इससे कहीं अधिक गणना यह है कि सरकार ने अपनी तमाम आर्थिक दिक्कतों तथा वित्तीय बाधाओं के बीच कर्मचारियों की हिस्सेदारी सुनिश्चित की है। पिछले कुछ समय से कर्मचारी वर्ग की ओर से यह दबाव रहा है कि उनके खाते में विभिन्न भुगतान किए जाएं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उक्त घोषणा करने से पूर्व हिमाचल की आर्थिक स्थिति, केंद्र के व्यवहार तथा सरकार के विभिन्न प्रयासों का जिक्र किया है। यह मानना पड़ेगा कि सरकार को चलाने का सबसे अधिक खर्चा सरकारी कर्मचारी व पेंशनभोगियों के खाते में जाता है। सरकार अपने चौथे वर्ष की लागत में मनोहारी होने का हर रंग आजमा सकती है और इसकी एक शुरुआत हम महंगाई की किस्त में देख सकते हैं। इससे पहले मंत्रिमंडल की बैठक में रिक्त पदों की भरपाई में सैकड़ों पदों पर नियुक्तियों का रास्ता खोला गया है। हम पहले भी कह चुके हैं कि अब सौगातों की फेहरिस्त में सरकार अपने हर कदम से चौंकाएगी। मसलों और मुद्दों पर नई दृष्टि और समाधानों की तीव्रता में सरकार अपना कद दिखाएगी। यह दीगर है कि अभी आर्थिक बेडियां टूटी नहीं हैं और राज्य को उधार उठाने की दरकार रहती है, फिर भी चुनाव की राह पर निकलने से पहले हर हिसाब में खर्च खड़ा होगा।

सरकार अपने हर तर्क में व्यवस्था परिवर्तन का जोखिम उठाती है और इसी तुलना में सियासी



माहौल बनाती है। बेशक आर्थिक संसाधनों की तलाश में सरकार ने कुछ अहम फैसले लिए, लेकिन आत्मनिर्भर होने का रास्ता बहुत दूर है। सरकार जल, जंगल और पर्यावरण से अपने अधिकारों की तलाश कर रही है। राज्य की संपत्तियों में अपना हिस्सा तय करते हुए वाइल्ड फ्लावर हॉल की तश्तरी में आए 400 करोड़ तथा विद्युत परियोजनाओं को नई कलम से लिखते समझौते आशा जगाते हैं। बहरहाल आत्मनिर्भरता के मायनों में सरकार की अपनी प्राथमिकताएं हो सकती हैं, लेकिन बढ़ते कर्ज का हिसाब अगर एक लाख करोड़ के आंकड़े को छू रहा है, तो आर्थिक दृश्य सहम जाते हैं। स्वयं मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि बजट का 70 फीसदी हिस्सा कर्मचारी वेतन-भत्ते, पेंशन और देनदारियों में खर्च होता है, तो बाकी मसलों, तरक्की के हाथों और ऋण बोझ से मुक्त होने के लिए कहां से आएगा धन। सोलहवें वित्तायोग की कचहरी पहले ही हिमाचल से विशेष राज्य के दर्जा के खिलाफ आरडीजी को मना कर चुकी है। वैसे भी प्रदेश को यह आदत नहीं कि कुछ शुल्क बढ़ाया जाए, हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी सेवाओं की फीस दर बढ़ रही है। ऐसे में निजी निवेश, स्वरोजगार और व्यापार को प्रोत्साहित करती योजनाएं बनें, तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, वरना हिमाचल में सरकारी नौकरी की आचार संहिता पहले ही राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक नियुक्तियों के कारण आप्रसंगिक है। बहरहाल प्रदेश के खजाने ने सरकारी कार्यालयों में कार्यरत लोगों के लिए कालीन बिछाया है। यह दीगर है कि ऐसे कालीनों के नीचे न वास्तविकता के कांटे छुपते हैं और न ही आर्थिक विडंबनाओं की कीलें टूटती हैं।

विचार

भारत और यूरोपीय देशों की तुलना नहीं

कुलदीप चंद अग्निहोत्री

लेखक

अल्बानिया में सुप्रीम कोर्ट को ही आग की लपटों के हवाले कर दिया गया। वे दंगई, हिंसाई 'रावण' नहीं, तो कौन हैं? बेशक आरोप थे कि कोर्ट कथित भ्रष्ट प्रधानमंत्री की मदद कर रही थी। बेशक यह 'रावणत्व' भारत के लिए भी चेतावनी है, लेकिन हमारी सर्वोच्च अदालत पर ऐसा कोई धब्बा नहीं है। हालांकि सात दशकों के स्वतंत्र भारत में मजदूरों, किसानों, शिक्षकों, आदिवासियों आदि ने अनगिनत आंदोलन किए हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ, 'नर्मदा बचाओ' पर, जल-संकट को लेकर भी आंदोलन किए गए हैं। लोकतंत्र में आंदोलन अनिवार्य और अपरिहार्य हैं, लेकिन आज तक किसी स्थानीय, जिला अदालत को भी आग के हवाले करने का 'रावणत्व' सामने नहीं आया है।

'विजयादशमी' पर्व पर रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण के पुतले इस बार भी जलाए गए। खुशफहमी पाल ली गई कि यह अधर्म पर धर्म, बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य, अहंकार पर मर्यादा की जीत है, लेकिन रावण तो हर साल जिंदा हो उठता है। आज भी जिंदा, हमारे बीच है। क्या रावण अजेय, अमर है? उसका दहन नहीं किया जा सकता! दुनिया भर में अशांति, उपद्रव, दंगे, युद्ध, मारकाट, आगजनी और अंततः विध्वंस का 'रावण' वाकई जिंदा है! जिस यूरोप को अपनी सभ्यता, संस्कृति, सम्पन्नता पर गुरूर होता था, आज उसी के देशों-फ्रांस, अल्बानिया, स्पेन, इटली, बेल्जियम-में जंग और लूटपाट के हालात हैं। अल्बानिया में सुप्रीम कोर्ट को ही आग की लपटों के हवाले कर दिया गया। वे दंगई, हिंसाई 'रावण' नहीं, तो कौन हैं? बेशक आरोप थे कि कोर्ट कथित भ्रष्ट प्रधानमंत्री की मदद कर रही थी। बेशक यह 'रावणत्व' भारत के लिए भी चेतावनी है, लेकिन हमारी सर्वोच्च अदालत पर ऐसा कोई धब्बा नहीं है। हालांकि सात दशकों के स्वतंत्र भारत में मजदूरों, किसानों, शिक्षकों, आदिवासियों आदि ने अनगिनत आंदोलन किए हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ, 'नर्मदा बचाओ' पर, जल-संकट को लेकर भी आंदोलन किए गए हैं। लोकतंत्र में आंदोलन अनिवार्य और अपरिहार्य हैं, लेकिन आज तक किसी स्थानीय, जिला अदालत को भी आग के हवाले करने का 'रावणत्व' सामने नहीं आया है। हालांकि सात दशकों के स्वतंत्र भारत में मजदूरों, किसानों, शिक्षकों, आदिवासियों आदि ने अनगिनत आंदोलन किए हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ, 'नर्मदा बचाओ' पर, जल-संकट को लेकर भी आंदोलन किए गए हैं। लोकतंत्र में आंदोलन अनिवार्य और अपरिहार्य हैं।

भारत में व्यापक विविधता है, फिर भी राष्ट्र के तौर पर



एकता, अखंडता है। यह एकजुटता निस्वार्थ है, लेकिन देश में संजय राउत सरीखे 'रावण' भी हैं। उन्होंने अल्बानिया की जलती सुप्रीम कोर्ट का संदर्भ साझा किया और कहा कि खासकर भारत को सबक सीखना चाहिए। क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना का यह राज्यसभा सांसद हमारी सर्वोच्च अदालत और उसके जरिए भारत की मोदी सरकार को धमकी दे रहा है? वैसे संजय राउत एक कुंठित, बेलगाम, दुराग्रही नेता हैं, लिहाजा उनके बयान का जिक्र ही काफी है। बहरहाल भारत और यूरोपीय देशों की तुलना नहीं की जा सकती। पूरे यूरोप की आबादी करीब 74.35 करोड़ है। अल्बानिया मात्र 27.5 लाख की आबादी का छोटा-सा, बौना देश है। फ्रांस हमारे उप्र का एक चौथाई देश है। अलबत्ता वहां औसतन 27 लाख रुपए प्रति छात्र की शिक्षा पर सरकार खर्च करती है, जबकि भारत में यह औसत 27,000 रुपए भी नहीं है। यदि फिर भी फ्रांस धधक, लुट रहा है, हिंसाग्रस्त है, तो उसके राजनीतिक कारण भी संभव हैं। यूरोपीय देशों में शरणार्थियों की समस्या अत्यंत भीषण, हिंसक है। आस्तीन में सांप उन्होंने ही पाले थे। हालांकि भारत में भी स्कूल और शिक्षा व्यवस्थाओं की बदहाली है, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और आर्थिक असमानताएं हैं। उन्हें लेकर आंदोलन भी किए जाते रहे हैं, लेकिन भारत कभी भी 'रावण' नहीं बना, क्योंकि औसत भारतीय के संस्कार और सोच देश-विरोधी नहीं हैं। बहरहाल संघ-प्रमुख ने जो मुद्दे उठाए हैं, उनके जो कथन हैं, वे इसलिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वह मोदी सरकार के भी संरक्षक हैं।'विजयादशमी' पर्व पर रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण के पुतले इस बार भी जलाए गए। खुशफहमी पाल ली गई कि यह अधर्म पर धर्म, बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य, अहंकार पर मर्यादा की जीत है, लेकिन रावण तो हर साल जिंदा हो उठता है। आज भी जिंदा, हमारे बीच है। क्या रावण अजेय, अमर है? उसका दहन नहीं किया जा सकता! दुनिया भर में अशांति, उपद्रव, दंगे, युद्ध, मारकाट, आगजनी और अंततः विध्वंस का 'रावण' वाकई जिंदा है! जिस यूरोप को अपनी सभ्यता, संस्कृति, सम्पन्नता पर गुरूर होता था, आज उसी के देशों-फ्रांस, अल्बानिया, स्पेन, इटली, बेल्जियम-में जंग और लूटपाट के हालात हैं। अल्बानिया में सुप्रीम कोर्ट को ही आग की लपटों के हवाले कर दिया गया। वे दंगई, हिंसाई 'रावण' नहीं, तो कौन हैं? बेशक आरोप थे कि कोर्ट कथित भ्रष्ट प्रधानमंत्री की मदद कर रही थी। बेशक यह 'रावणत्व' भारत के लिए भी चेतावनी है, लेकिन हमारी सर्वोच्च अदालत पर ऐसा कोई धब्बा नहीं है। हालांकि सात दशकों के स्वतंत्र भारत में मजदूरों, किसानों, शिक्षकों, आदिवासियों आदि ने अनगिनत आंदोलन किए हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ, 'नर्मदा बचाओ' पर, जल-संकट को लेकर भी आंदोलन किए गए हैं। लोकतंत्र में आंदोलन अनिवार्य और अपरिहार्य हैं।

विचार

सियासी समीक्षा का दौर शुरू

भूपिंद्र सिंह

लेखक

अगले विधानसभा चुनाव की कुछ शर्तें तय हो रही हैं और यह एक रूटीन सी है कि सत्ता अपना चौथा साल इस लिहाज से जाहिर करे। विपक्ष का कदमताल अपनी संगठन की ताकत का हिसाब दे। हिमाचल में एक हिसाब केंद्र बनाम राज्य की पटरी पर खड़े अवरोधों का भी होगा। कर्मचारियों की शिनाख्त में सरकार के फैसलों का महाकुंभ दिखाई दे, इसलिए वहीं पुरानी गंगा में कुछ पाप धुलेंगे।



राजनीति का अपना ढर्रा है और इसलिए मुकाबला यह कि किस पार्टी में अधिक गुट हैं। अनूठे मिलन समारोह और आतंरिक रार की तहों में फिसलते समीकरण। कुल मिलाकर अब राजनीतिक समीक्षा का यह दौर मुकाबलों की नई फेहरिस्त पैदा करेगा। कांग्रेस और भाजपा के बीच संयोजकों के तहत किलेबंदियां। भाजपा अपने प्रचार के औजार पैने कर रही है, तो कांग्रेस की जमात 'वोट बचाओ, देश बचाओ' के साहसिक कदम उठाती हुई दिखाई देगी। महत्त्वपूर्ण यह नहीं कि सियासी युद्ध किस करवट बैठेंगे, बल्कि यह है कि सत्ता अपना राजनीतिक अनुष्ठान कैसे करती है। सरकार के पास रिपोर्ट कार्ड है, जिसका इस्तेमाल पंचायत, शहर से समूचे प्रदेश तक हो सकता है। नई पंचायतों की गणना के तिलक अगर ठौर बनाने तक सफल हो गए तो यह कवायद याद की जाएगी। नगर निकाय अगर नागरिक सहूलियतों में इजाफा कर पाएंगे, तो सरकार की पदवी संभल जाएगी। ऐसे में सरकार को अपने फैले हुए प्रयासों को समेटना होगा और बजट की लागत से खड़े किए गए स्तंभों को अच्छे से पेंट करना होगा। बेशक सरकार ने कई मॉडल बनाने शुरू किए, जिन्हें अब पूर्ण रूप से पेश करना होगा। गारंटियों के राजनीतिक दौर अब आगामी चुनाव की फतह को प्रदर्शित करने का जरिया बन सकते हैं और सरकार अगर इसे फार्मूला रेस की तरह निभा पाई तो अंतर देखा जाएगा। राजनीति खुद को देखने के साथ-साथ कर्मचारी वर्ग को कितना देख पाती है, यह एक गोल्डन रूल सदा रहा है।

हिमाचल के विधानसभा चुनावों से मुख्यमंत्रियों की ताकत ऐसे फैसलों में महसूस होती रही है, जो अति उदार और लोकप्रियता के मानकों पर आधारित होती है। जाहिर है सुखविंदर सुक्खू भी अपनी महिमा के अनुरूप जनता की ऐसी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। अंततः जनता क्या देखना चाहेगी यह तय करना विपक्ष में जिम्मेदारी का एहसास रहा है। बतौर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर सरकार के विरोध में अपनी पताका फहराते हुए कहां पहुंचे, इसका अवलोकन ही बता पाएगा कि भाजपा में कौनसा गुट भारी है। कम से कम यह तो दिखाई देता है कि जयराम ठाकुर की मुलाकातें दिल्ली में प्रधानमंत्री के कक्ष में सुकून से होती हैं। एक गणित उन्हें दिल्ली दरबार से तमाम उत्तराधिकार और दायित्व प्रदान करता हुआ दिखाई देता है। दूसरी तरफ राजनीतिक व प्रशासनिक तौर पर सशक्त बनकर उभरे सुखविंदर सिंह सुक्खू भी कांग्रेस के मॉडल में अपनी जगह की मजबूती से आगामी चुनाव को देख रहे हैं। ऐसे में क्या पिछले चार साल का राजनीतिक दौर ही आगामी चुनाव का आमना सामना करेगा। क्या प्रदेश के पूर्व में सुखविंदर सिंह सुक्खू या पश्चिम में जयराम ठाकुर होंगे या उत्तर-दक्षिण ध्रुव बदलेंगे। जो भी हो चार वर्ष के खाके में सत्तारूढ़ दल की सारी कर्मठता, कार्यसंस्कृति और क्षमता सुक्खू के हाथों में है। दूसरी ओर जयराम ठाकुर भी अपनी जमीन से अगर इंच भी पीछे नहीं हटे, तो आगे बढ़ते उनके अरमान हमेशा दो दो हाथ करते रहे हैं। अब देखना यह है कि भाजपा अपने केंद्र से कितनी शक्ति-कितनी ऊर्जा जयराम को देती है या केंद्र सरकार के कौन से फैसले हिमाचल को मरहम लगाते हैं। दूसरी ओर सुक्खू का रिपोर्ट कार्ड 68 विधानसभा क्षेत्रों में कितनी ग्रीन बसें या हेलिकॉप्टर उड़ाता है। प्रदेश में इस बार फोरलेन का जाल, उड़ान योजना की उड़ान या बनते संवरते गगल एयरपोर्ट का भी हिसाब होगा। यही हिसाब सरकार के मंत्रियों और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच भी होगा। यहां दोनों पार्टियों की अपनी-अपनी परंपराओं और पृष्ठ भूमि पर भी बहस का दौर शुरू हो रहा है। क्या दूसरी बार सुक्खू या हर बार जयराम के बीच अंतिम वर्ष की पैमाइश शुरू हो रही है या होगी, यह काफी हद तक हिमाचल के मध्यवर्गीय मतदाता पर निर्भर करेगा।



जीवन में प्यार की शक्ति का रहस्य अजीबोगरीब है। इसकी ऊर्जा अनंत है। इसके आभास मात्र से आप सक्रिय हो उठते हैं। भरपूर शक्ति के साथ काम में जुट जाते हैं। यही अहसास अगर जीवन संगिनी के साथ होने का हो तो तय है कि आप इसके बल पर अपनी जिंदगी में किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं।

जरा छूकर देखो

सामान्यतया जीवन संगिनी के प्रेम को लेकर भारतीय समाज में ढेरों धारणाएं हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर जीवनसाथी के साथ व्यावहारिक जीवन सहज है तो उससे बेहतर जिंदगी नहीं हो सकती। वास्तव में है भी ऐसा, क्योंकि तरोताजा बने रहने और पूरी क्षमता के साथ काम करने के लिए सुकून सबसे अहम चीज है। इसे आप पैसों से नहीं खरीद सकते। इसे आप अपने व्यवहार और आपसी समझ से ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि प्यार केवल भावनाओं का लेना-देना नहीं, बल्कि इसमें स्पर्श का योगदान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ समय पहले ही अमेरिका में हुए एक शोध में पाया गया है कि कोई भी महिला या लड़की किसी पुरुष को अगर प्यार से छू ले या पुरुष के पीठ का स्पर्श मात्र कर दे तो उसे सुकून मिलता है। उसका मानसिक तनाव कुछ कम हो जाता है। वह दुगुनी साहस के साथ चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए उठ खड़ा होता है।

स्पर्श में जादू

महिलाओं के स्पर्श में वह जादू है, जो दवा का काम करता है। महिलाओं के छुअन मात्र से पुरुष खुद को सुरक्षित महसूस करने लगते हैं। कोई भी खतरा मोल लेने को तैयार हो जाते हैं। सुरक्षा का यही बोध उन्हें अपने जीवन में निश्चिंत रहने और हर जिम्मेदारी को

सजने-संवरने पर रोज दीजिए 18 मिनट

ज्यादातर लोगों की हमेशा यह जानने में दिलचस्पी होती है कि महिलाएं घर से बाहर निकलने से पहले आइने के सामने कितना समय लगाती हैं। अब तक महिलाओं के बारे में यह पता नहीं चल सका है। लेकिन इसका जवाब मिल गया कि ब्रिटेन में पुरुषों को सजने-संवरने में कितना समय लगता है।



एक शोध में पता चला है कि औसत ब्रिटिश पुरुष रोज सुबह तैयार होने या संजने-संवरने में पूरे 18 मिनट खर्च करते हैं। ब्रिटेन में खुद की खूबसूरती पर गुमान करने वाले पुरुषों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये पुरुष अपने जीवनकाल में 5,105 मिनट या अपनी जिंदगी साढ़े तीन से कुछ ज्यादा दिन आइने के सामने खुद को आकर्षक बनाने में व्यतीत करते हैं। यह सर्वेक्षण 1,012 पुरुषों पर किया गया था। इनमें से 54 प्रतिशत लोगों ने स्वीकार किया कि वे अपने साथी को खुश करने के लिए ऐसा करते हैं।







दूसरों से स्मार्ट लगें

एक चौथाई पुरुषों का कहना था कि वे साथी पुरुषों से श्रेष्ठ दिखने की प्रतिस्पर्धा में ऐसा करते हैं। 38 प्रतिशत पुरुषों का कहना था कि वे अपने व्यक्तित्व को निखारने या खुद को खूबसूरत बनाने के संबंध में बहुत थोड़ा ही जानते हैं। उनका कहना था कि उन्हें इसके नुस्खे पूछने में झिझक महसूस होती है। वेल्श में सबसे ज्यादा, 70 प्रतिशत पुरुषों ने स्वीकार किया कि वे खूबसूरत दिखने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। इससे विपरीत वेस्ट मिडलैंड्स में पुरुषों को तैयार होने में केवल 10 मिनट का समय लगता है। उनका कहना था कि संजने-संवरने में 18 मिनट जरूर लगते हैं, लेकिन जब किसी से पहली बार मिलते हैं तो वह तारीफ करता है।



तैयार करें परफेक्ट ट्रेवल ब्यूटी किट

मेकअप और जरूरी सामान रखने के लिए ज्यादातर महिलाओं के पास ब्यूटी किट होती है। मगर, मुश्किल तब आती है जब आपको इस ब्यूटी किट को अपने साथ ले जाना हो और आपको यह समझ न आए कि क्या रखें और क्या न रखें। तो अब जानिए हर ओकेजन के हिसाब से कैसे तैयार करें ब्यूटी किट।



शादी के लिए

- शादियों के लिए जब भी ब्यूटी किट तैयार करें, तो उसमें अपने पसंदीदा परफ्यूम के लिए जगह बनाएं।
- सहेली की बिदाई के दौरान कई बार आंखें नम हो जाती हैं, इसलिए एक वाटरप्रूफ मस्कारा रखना न भूलें।
- शादी में कई कार्यक्रम होते हैं और हर कार्यक्रम में नया हेयरस्टाइल होना जरूरी है। इसलिए एक हेयर स्ट्रेटनर और एक हेयर कर्लर रखना न भूलें।

पार्टी के लिए

- हेयर एक्सटेंशन, हेयर मस्कारा साथ रखें, ताकि आपके बाल सभी से ज्यादा स्टाइलिश नजर आ सकें।
- अगर आपके बाल काफी लंबे हैं, तो आप हेयर मूस को साथ रखें, इससे आपके बाल अधिक घने और चमकदार दिखते हैं।
- एक हेयर रिमूवल क्रीम और रेजर भी पैक करना न भूलें
- क्लींजिंग मिल्क भी जरूर रखें, ताकि आप पार्टी मेकअप को ठीक तरह से अपने चेहरे से हटा सकें।

पिकनिक के लिए

- क्योंकि आप पूरा समय बाहर रहने वाली हैं तो अपने बैग में एसपीएफ 30 सनस्क्रीन लोशन रखना न भूलें।
- इस दौरान आपको कई वेट वाइप्स या टिशूज भी पैक करने चाहिए, क्योंकि पिकनिक पर भागा-दौड़ काफी होती है।
- एक अच्छा हैंड सेनिटाइजर रखना न भूलें। क्योंकि हाथ बार-बार धोना संभव नहीं होता।

अब जींस पर साड़ी बांधिये

फैशन के इस दौर में साड़ी को अलग ढंग से बांधने के तरीके से अवगत कराया जा रहा है। पारंपरिक परिधानों को नए अवतार में पेश करने के विषय में पूछने पर बताया छरहरी और लंबी दिखने वाली लड़कियां साड़ी पर बेल्ट लगा सकती हैं। इसमें आप अधिक युवा और आकर्षक नजर आएंगी। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के लिए शादी का जोड़ा तैयार किया था ताहिलयानी ने। उनका कहना है कि सुनहरी या चांदी की रंगत वाली बेल्ट पारंपरिक कमरबंध के स्थान पर आधुनिक कमरबंध के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। अब जींस के ऊपर साड़ी बांधना नए फैशन में है।



अब एक फैशन में पारंपरिक साड़ी को अलग-अलग तरह से बांधकर उसे अब एक नये ढंग व आधुनिक रूप दिया जा सकता है। डिजाइनरों के अनुसार इन दिनों जींस के ऊपर साड़ी बांधने या साड़ी पर बेल्ट लगाने का फैशन है। युवा लड़कियों ने साड़ी बांधने के इन तरीकों का स्वागत किया है।

बिंदास लुक के लिए टशनी ट्राउजर



लेटेस्ट फैशन

टाइट फिटेड ट्राउजर व जींस वार्डरोब से बाहर हो चुके हैं और इनकी जगह वाइड लेग्स ट्राउजर व फ्लेयर लेग्स जींस ने ले ली है। पिछले दिनों आईं कई फिल्मों में वाइड लेग्स ट्राउजर व फ्लेयर लेग्स जींस खूब दिखाई दीं। यदि आप भी कुछ नई ड्रेस तलाश रही हैं, तो इन्हें ट्राई कर सकती हैं।

रफ एंड टफ ड्रेस

वाइड लेग्स ट्राउजर व फ्लेयर लेग्स जींस रफ एंड टफ स्टाइल है, जो आपको ग्लैमरस व बोल्ड लुक देता है। लड़कियां बिंदास लुक चाहती हैं, तो उनके लिए यह परफेक्ट ड्रेस है। इस आउटफिट पर चौड़ी बेल्ट भी फैशन में है। इसमें आप लेदर या फिर ट्राउजर के फैब्रिक से ही मैच करती बेल्ट डिजाइन करवा सकती हैं। यदि आप हाई वेस्ट वाइड लेग्स ट्राउजर पहन रही हैं, तो उस पर चौड़ी बेल्ट पहनें। इससे लुक अच्छा आएगा।

डिजाइन व पैटर्न

आप इन्हें कई स्टाइल में खरीद सकती हैं। इसमें हाई वेस्ट, लो वेस्ट, प्लेटेड वगैरह स्टाइल खास हैं। इसके साथ फिटेड टी-शर्ट, फ्रील शर्ट, शॉर्ट जैकेट को कोट के साथ मैच करके पहना जा सकता है। आप वाइड लेग्स ट्राउजर व फ्लेयर लेग्स जींस की चौड़ाई अपनी चॉइस के मुताबिक कम या ज्यादा भी करवा सकती हैं।

1980 का ट्रेंड

वाइड लेग्स ट्राउजर व फ्लेयर लेग्स जींस नया स्टाइल नहीं है। यह 1980 का फैशन है, जो नए अंदाज के साथ लौट आया है। डिजाइनर्स ने इसमें अपनी क्रिएटिविटी यूज करके इसे और भी स्टाइलिश व फैंसी बना दिया है। फैशन डिजाइनर कहना है कि लूज ड्रेसेज ही ज्यादा कम्फर्टेबल होती हैं। ऐसे में वाइड लेग्स ट्राउजर व फ्लेयर जींस बेस्ट ड्रेस हैं।



यदि आप बिंदास व रफ एंड टफ लुक चाहती हैं, तो वाइड लेग्स ट्राउजर व फ्लेयर लेग्स जींस ट्राई कर सकती हैं। यह नया ट्रेंड है और इन दिनों लड़कियों के बीच बेहद पॉपुलर है। एक नजर डालते हैं इसके ट्रेंड पर।

नए प्रिंटेट

यदि प्रिंट की बात की जाए तो इसमें प्लेन, प्रिंटेड, एम्ब्रॉयडरी वर्क भी ट्रेंड में हैं। कई फैशन डिजाइनर्स ने वाइड लेग्स ट्राउजर व फ्लेयर लेग्स जींस में कई डिजाइन पेश किए हैं। इसमें शीयर फैब्रिक में भी आपको ट्राउजर मिल जाएंगे, जो पूरी तरह नया स्टाइल है।

बेस्ट कलर

आप लाइट कलर के ट्राउजर ही चुनें। वाइट, लाइट स्काई, पिंक, पर्पल, ग्रे, यलो व डल ब्लैक वगैरह प्रिफर करें। वहीं फ्लेयर लेग्स जींस में ब्लू, मस्टर्ड व ग्रीन कलर ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं।

न्यूज इन शॉर्ट

'शेरपार-मानपुर-कोहका सड़क के अधूरे और गुणवत्ताहीन निर्माण कार्यों तथा उखड़ी सड़क पर ठेकेदारों को नोटिस, पीडब्ल्यूडी ने 15 दिनों में मांगा जवाब'

रायपुर, लोक निर्माण विभाग ने शेरपार-मानपुर-कोहका सड़क के अधूरे और गुणवत्ताहीन निर्माण कार्यों तथा उखड़ी सड़क पर दो ठेकेदारों को नोटिस जारी किया है। विभाग ने राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र के अधिकारियों के निरीक्षण और कार्यों की जांच के बाद सड़क निर्माण की गुणवत्ता, रखरखाव, सड़क सुरक्षा और मानकों के अनुरूप निर्माण नहीं पाए जाने पर यह कार्रवाई की है। दोनों ठेकेदारों को 15 दिनों के भीतर जवाब देने कहा गया है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय राजमार्ग की यह सड़क अभी परफॉर्मेंस गारंटी में है।

परफॉर्मेंस गारंटी की इस सड़क के निर्माण के बाद सतह पर क्षति और रखरखाव में लापरवाही पर विभाग ने राष्ट्रीय राजमार्ग उप संभाग बालोद के सभी छह उप अभियंताओं के भी विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सभी उप अभियंताओं को तीन दिनों में अपना प्रतिवाद प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। संतोषजनक जवाब नहीं पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी।



'डिजिटल सुविधा से एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल रहे जरूरी दस्तावेज, शासकीय सेवाओं तक पहुंच हुई सुगम'

रायपुर, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संचालित सेवा सेतु जैसी डिजिटल पहल का उद्देश्य नागरिकों को शासकीय सेवाओं से जोड़ना और जरूरी दस्तावेजों की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाना है। सेवा सेतु से नागरिकों को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने और शासकीय सेवाओं तक उनकी पहुंच आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसी कड़ी में मुंगेली जिले के तखतपुर निवासी मानसी चंद्राकर का सेवा सेतु के माध्यम से जाति, निवास एवं आय प्रमाण पत्र बना। इन प्रमाण पत्रों की आवश्यकता विद्यार्थियों की पढ़ाई, विभिन्न शासकीय योजनाओं और अन्य जरूरी कार्यों में पड़ती है। ऐसे में सेवा सेतु के माध्यम से आवेदन एवं प्रमाण पत्र संबंधी सुविधा मिलने से नागरिकों को आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने में मदद मिल रही है। मानसी ने सेवा सेतु के संचालन के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और शासन-प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि ऐसी सुविधाएं नागरिकों के लिए बेहद उपयोगी और कारगर हैं।

स्वास्थ्य सुविधाओं को मिली मजबूती

सुकमा, जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में जिला प्रशासन ने एक और महत्वपूर्ण पहल की है। खनिज न्यास निधि (डीएमएफ) से दो नए शव वाहन क्रय किए गए हैं, जिनमें एक जिला चिकित्सालय सुकमा तथा दूसरा विकासखंड कोंटा को उपलब्ध कराया गया है। कलेक्टर श्री अमित कुमार ने शनिवार को दोनों नवीन शव वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पहल से जिले में शव परिवहन की व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और जरूरतमंद परिवारों को कठिन परिस्थितियों में राहत प्रदान करने में मदद मिलेगी। जनहित को प्राथमिकता, जरूरतमंद परिवारों को मिलेगी बेहतर सुविधा नए शव वाहनों की उपलब्धता से जिला चिकित्सालय सुकमा और कोंटा क्षेत्र में शव परिवहन की सुविधा अधिक सुलभ बनाने में मदद मिलेगी।

सारंग हेलीकॉप्टर एयर शो की तैयारियों की कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने की समीक्षा

सुरक्षा, यातायात, चिकित्सा एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण करने के निर्देश

एक सत बुलेटिन ➤ रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026 के अवसर पर नवा रायपुर अटल नगर स्थित सेंध लेक क्षेत्र में आयोजित होने वाले सारंग हेलीकॉप्टर एयर शो की तैयारियों को लेकर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सभाकक्ष में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारतीय वायु सेना के वरिष्ठ अधिकारियों सहित जिला प्रशासन, नगर निगम तथा विभिन्न संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में एयर शो के सफल, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित आयोजन के लिए की जा रही तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई तथा सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, चिकित्सा सुविधाओं, आपातकालीन सेवाओं और दर्शकों की सुविधा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।

बैठक में आयोजन स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाने, यातायात का सुचारु संचालन सुनिश्चित करने तथा दर्शकों एवं अतिथियों की सुविधा के लिए आवश्यक प्रबंध करने पर विशेष जोर दिया गया। इस दौरान पुलिस सहायता, चिकित्सा सुविधाओं, आपातकालीन सेवाओं, परिवहन व्यवस्था और पार्किंग



प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की गई। साथ ही ड्रॉप जोन की लेबलिंग, आयोजन स्थल पर प्रवेश एवं आवागमन की व्यवस्था तथा किसी भी आपात परिस्थिति से निपटने के लिए आवश्यक इंतजाम समय पर सुनिश्चित करने के संबंध में चर्चा की गई।

एयर शो के सफल संचालन के लिए आयोजन स्थल पर आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता को लेकर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। इसमें विद्युत आपूर्ति, सॉफ्ट ग्राउंड, मेंटेनेंस, मोबाइल टॉयलेट, कार्यालयीन कार्यों के लिए आवश्यक स्थान तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था शामिल रही। अधिकारियों ने आयोजन स्थल की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने और कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए संबंधित विभागों के बीच समन्वय बनाए रखने पर चर्चा की। बैठक में अतिथियों के आगमन एवं स्वागत, परिवहन और पार्किंग की समुचित व्यवस्था तथा एयर शो के व्यापक प्रचार-प्रसार से जुड़े विषयों की भी समीक्षा की गई। आयोजन में शामिल होने वाले अतिथियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और दर्शकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक प्रबंध करने पर बल दिया गया। साथ ही आयोजन स्थल पर चिकित्सा सहायता एवं अन्य आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा संबंधित टीमों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने के महत्व पर भी चर्चा हुई।

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा की जा रही तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि सारंग हेलीकॉप्टर एयर शो जैसे महत्वपूर्ण आयोजन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समयबद्ध तरीके से पूर्ण की जानी चाहिए। उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने तथा सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य सेवाओं, परिवहन, विद्युत आपूर्ति और अन्य बुनियादी सुविधाओं से संबंधित तैयारियों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने पर जोर दिया। आयोजन के दौरान आम नागरिकों एवं दर्शकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित एवं प्रभावी बनाए रखने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया।

छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026 के अवसर पर आयोजित होने वाला सारंग हेलीकॉप्टर एयर शो राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण आकर्षण होगा। इसे देखते हुए आयोजन से संबंधित सभी तैयारियों की नियमित समीक्षा, विभागीय जिम्मेदारियों का प्रभावी निर्वहन और समय पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

बैठक में नगर निगम रायपुर के आयुक्त श्री संबित मिश्रा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कुमार बिस्वरंजन, भारतीय वायु सेना के वरिष्ठ अधिकारी तथा स्वास्थ्य विभाग, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए), परिवहन विभाग, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

केल्हारी में मेडिकल स्टोर के संचालन पर सवाल, वन भूमि पर कथित कब्जे और दवा बिक्री की निष्पक्ष जांच जरूरी

बिना वैध दस्तावेज दवाइयों की बिक्री का आरोप, मरीजों की सुरक्षा से खिलवाड़ तो नहीं

एक सत बुलेटिन ➤ एमसीबी

दवाइयां किसी दुकान में बिकने वाला सामान्य सामान नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी और स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण वस्तु हैं। इसलिए दवाइयों की बिक्री के लिए निर्धारित नियमों, वैध दस्तावेजों और आवश्यक लाइसेंस का पालन करना अनिवार्य है। यदि कहीं बिना वैध दस्तावेजों के दवाइयां बेचे जाने की शिकायत सामने आती है, तो यह केवल नियमों के उल्लंघन का मामला नहीं, बल्कि जनस्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर विषय है।

एमसीबी जिले के केल्हारी क्षेत्र में संचालित छत्तीसगढ़ मेडिकल स्टोर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि कांग्रेस के पूर्व जनपद सदस्य से संबंधित इस मामले में वन विभाग की जमीन पर कथित कब्जा कर मेडिकल स्टोर संचालित किया जा रहा है। इसके साथ ही बिना वैध दस्तावेजों के दवाइयों की बिक्री किए जाने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित पक्ष का आधिकारिक बयान सामने आना अभी बाकी है।

सरकारी जमीन पर दुकान, आखिर किसकी अनुमति से?

यदि संबंधित भूमि वास्तव में वन विभाग के स्वामित्व में है, तो सबसे पहले भूमि के दस्तावेजों, सीमांकन और कब्जे की स्थिति की जांच होनी चाहिए। क्या दुकान के संचालन के लिए संबंधित विभाग से अनुमति ली गई है? क्या निर्माण वैधानिक प्रक्रिया के तहत हुआ है? इन सवालों का जवाब दस्तावेजों और विभागीय जांच से ही सामने आ सकता है।

सरकारी जमीन किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं होती। उसकी सुरक्षा और संरक्षण की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होती है। यदि जांच में अवैध कब्जा प्रमाणित होता है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन बिना जांच किसी को दोषी ठहराना भी उचित नहीं है।





बिना वैध लाइसेंस दवा बिक्री का आरोप गंभीरदवाइयों की बिक्री निर्धारित कानूनी प्रावधानों के अधीन होती है। मेडिकल स्टोर के संचालन के लिए लागू नियमों के अनुसार आवश्यक औषधि लाइसेंस और अन्य निर्धारित शर्तों का पालन जरूरी है। ऐसे में यदि बिना वैध लाइसेंस या आवश्यक दस्तावेजों के दवाइयां बेचे जाने की शिकायत है, तो औषधि प्रशासन को इसकी जांच करनी चाहिए।

यह भी देखना जरूरी है कि दुकान में बेची जा रही दवाइयां अधिकृत स्रोत से खरीदी गई हैं या नहीं, दवाओं के भंडारण के नियमों का पालन हो रहा है या नहीं तथा जहां आवश्यक हो, वहां पंजीकृत फार्मासिस्ट की उपलब्धता सुनिश्चित है या नहीं।

दवा की गुणवत्ता, उसकी वैधता और सही तरीके से बिक्री का सीधा संबंध मरीजों की सुरक्षा से है। इसलिए ऐसी शिकायतों को नजरअंदाज करना जनहित के विरुद्ध होगा।

विभागीय चुप्पी या कार्रवाई, जनता जानना चाहती है जवाब

इस मामले में वन विभाग और औषधि प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण है। संबंधित अधिकारियों को शिकायत की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक स्थिति सार्वजनिक करनी चाहिए। यदि सभी दस्तावेज वैध हैं, तो तथ्य सामने रखे जाएं। यदि अनियमितताएं प्रमाणित होती हैं, तो संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जाए।

किसी व्यक्ति की राजनीतिक पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो, कानून का पालन सभी के लिए समान होना चाहिए। न किसी को राजनीतिक पहचान के कारण निशाना बनाया जाना चाहिए और न ही किसी को प्रभाव के आधार पर नियमों से छूट मिलनी चाहिए।

जनहित में जांच जरूरी, आरोपों पर नहीं बल्कि तथ्यों पर हो कार्रवाई

केल्हारी का यह मामला कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े करता है। क्या वन विभाग की जमीन पर मेडिकल स्टोर संचालित हो रहा है? क्या दुकान के पास दवाइयों की बिक्री के लिए वैध लाइसेंस है? क्या संबंधित विभागों ने कभी निरीक्षण किया है? यदि शिकायत सही है, तो अब तक क्या कार्रवाई हुई?

इन सवालों का जवाब केवल बयानबाजी से नहीं, बल्कि दस्तावेजों की जांच और निष्पक्ष कार्रवाई से मिलेगा।

संपादकीय निष्कर्ष- सरकारी जमीन की सुरक्षा और आम नागरिकों के स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में प्रशासन को जवाबदेह होना चाहिए। केल्हारी में मेडिकल स्टोर के संचालन, भूमि की वैधानिक स्थिति और दवाइयों की बिक्री से संबंधित आरोपों की समयबद्ध जांच कराई जाए। यदि अनियमितताएं प्रमाणित हों, तो नियमानुसार कार्रवाई हो; और यदि आरोप निराधार निकलें, तो यह तथ्य भी सार्वजनिक किया जाए।

क्योंकि जनहित के सवालों का जवाब दबाव या प्रभाव से नहीं, कानून, पारदर्शिता और प्रमाणों से मिलना चाहिए।

दवाएं सस्ती हों, ग्रामीणों तक पहुंचे इलाज, नकली दवाओं पर लगे रोक -राज्यपाल श्री डेका

एसोसिएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल टीचर्स ऑफ इंडिया के 28वें राष्ट्रीय अधिवेशन एपिकॉन-2026 में शामिल हुए राज्यपाल



एक सत बुलेटिन ➤ रायपुर

राज्यपाल श्री रमेन डेका ने कहा कि सस्ता इलाज, किफायती दवाएं और ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना देश की प्रमुख चुनौतियां हैं। इनके समाधान के लिए चिकित्सकों, फार्मासिस्टों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को मिलकर काम करना होगा। स्वास्थ्य और शिक्षा को केवल कारोबार नहीं, बल्कि समाजसेवा का माध्यम बनाया जाना चाहिए। उन्होंने नकली दवाओं पर रोक लगाने, भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों पर वैज्ञानिक शोध करने और छत्तीसगढ़ की वनौषधियों के पारंपरिक ज्ञान को सामने लाने पर जोर दिया।

राज्यपाल श्री डेका आज पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में एसोसिएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल टीचर्स ऑफ इंडिया (एपीटीआई) के 28वें राष्ट्रीय अधिवेशन एपिकॉन-2026 को संबोधित कर रहे थे। अधिवेशन का विषय 'फार्मा शिक्षक आत्मनिर्भर भारत के लिए फार्मासिस्ट तैयार करने का संकल्प' था। राज्यपाल ने कहा कि देश ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में प्रगति की है, लेकिन ग्रामीण आबादी तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना अब भी चुनौती है। दवाओं की कीमत आम आदमी की पहुंच में होनी चाहिए। चिकित्सकों को दवाएं लिखते समय मरीज की आर्थिक स्थिति का ध्यान रखना चाहिए और जहां संभव हो, कम कीमत वाली प्रभावी दवाओं के विकल्प अपनाने चाहिए। उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि चिकित्सकों और फार्मासिस्टों को गांवों तक पहुंचकर लोगों को जागरूक करना होगा। गर्भवती महिलाओं, माताओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना जरूरी है।

राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों, विशेषकर बैगा समुदाय के पास औषधीय पौधों और पारंपरिक उपचार पद्धतियों से जुड़ा महत्वपूर्ण ज्ञान है। इसका वैज्ञानिक अध्ययन और दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए। भारतीय चिकित्सा परंपराओं में उपलब्ध जानकारी की आधुनिक शोध के माध्यम से जांच कर उनकी उपयोगिता का आकलन करना जरूरी है।

नकली दवाओं को गंभीर खतरा बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे मरीजों के स्वास्थ्य और जीवन पर संकट पैदा होता है तथा चिकित्सा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कमजोर होता है। फार्मेसी के विद्यार्थियों, शिक्षकों और दवा उद्योग को दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और इंटरनेट का उपयोग ज्ञान बढ़ाने के लिए करने तथा मौलिक चिंतन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नैतिक मूल्यों को महत्व देने की अपील की।

फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉ. मोंटू एम. पटेल ने बताया कि बदलती तकनीक और उद्योग की जरूरतों के अनुरूप फार्मेसी पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मेडिकल डिवाइस जैसे विषय शामिल किए गए हैं। उन्होंने अनावश्यक एंटीबायोटिक के इस्तेमाल के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश के 42 स्थानों पर चलाए जा रहे अभियान की जानकारी दी।

पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सच्चिदानंद शुक्ला ने विश्वविद्यालय में चल रहे शोध कार्यों का उल्लेख करते हुए छत्तीसगढ़ के वन आधारित औषधीय संसाधनों से नए उत्पाद विकसित करने और फार्मेसी शोध को अन्य विज्ञान विषयों से जोड़ने की जरूरत बताई।

पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर ने अनुशासन बनाए रखने और आपात स्थिति में तत्परता से कार्रवाई करने के दिए निर्देश

बलरामपुर पुलिस लाइन में जनरल परेड का निरीक्षण, आपदा प्रबंधन की मॉक ड्रिल आयोजित

एक सत बुलेटिन ➤ बलरामपुर

बलरामपुर-रामानुजगंज जिले की पुलिस लाइन में शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर (भा.पु.से.) ने जनरल परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने परेड की सलामी ली और पुलिसकर्मियों के अनुशासन, वर्दी, शारीरिक दक्षता तथा परेड की गुणवत्ता का जायजा लिया।

परेड के दौरान पुलिस अधीक्षक ने पुलिसकर्मियों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहने, अनुशासन बनाए रखने तथा अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ करने के निर्देश दिए।

मॉक आपदा से निपटने की तैयारियों का किया अभ्यास





जनरल परेड के बाद आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इसमें आपातकालीन परिस्थितियों में पुलिस बल की त्वरित प्रतिक्रिया, राहत एवं बचाव कार्य, घायलों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने और यातायात व्यवस्था बनाए रखने का अभ्यास किया गया। साथ ही संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया भी दोहराई गई।

पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया कि आपदा के समय उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग करते हुए तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने आमजन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और राहत एवं बचाव कार्यों को तत्परता से संचालित करने पर जोर दिया। मॉक ड्रिल का उद्देश्य पुलिस बल को आपातकालीन परिस्थितियों से



निपटने के लिए तैयार रखना, कार्यक्षमता बढ़ाना तथा आपदा के समय जनसामान्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना रहा।

इस दौरान उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) प्रमोद किसपोट्टा, रक्षित निरीक्षक विमलेश कुमार देवांगन, प्रशिक्षु सूबेदार ज्योति साहू सहित पुलिस एवं नगर सेना के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

वाड्रफनगर में 40 लीटर महुआ शराब और 90 किलो लाहन जब्त, एक के खिलाफ मामला दर्ज,

अवैध शराब के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्रवाई, ग्राम चलगली में दबिश देकर हाथभट्टी महुआ शराब की जब्ती,

जिले में अवैध कच्ची शराब के निर्माण और बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए आबकारी विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 23 अक्टूबर को आबकारी वृत्त वाड्रफनगर की टीम ने ग्राम चलगली में कार्रवाई करते हुए 40 बल्क लीटर हाथभट्टी महुआ शराब और 90 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के निर्देश तथा जिला आबकारी अधिकारी शशांक शर्मा के मार्गदर्शन में अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत आबकारी टीम ने ग्राम चलगली निवासी रामजनम काशी के कब्जे से उक्त



शराब और महुआ लाहन बरामद किया। मामले में आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क)(च), 34(2) एवं 59(क) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। मामले की विवेचना आबकारी उपनिरीक्षक अभिषेक राजवाड़े द्वारा की जा रही है। इस कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक, मुख्य आरक्षक, आरक्षक, महिला नगर सैनिक और वाहन चालकों की सक्रिय भूमिका रही।

एक सत प्रयास जनकल्याण समिति के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक **अभिषेक शर्मा** द्वारा 202, भाटागांव चौराहा , रायपुर (छत्तीसगढ़) पिन 492015 से प्रकाशित एवं आसमा पब्लिशर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड , गॉस मेमोरियल हाल के पास , जयस्तंभ चौक, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित।

संपादक - रिज़वान आज़म, **समूह संपादक**- महेश कुमार तिवारी ईमेल - eksatbulletin@gmail.com R.N.I Number - CHHHIN/2020/78457 पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार ।